पूरा बेंच

ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, एस. एस. संधवालिया और एम. आर. शर्मा, जे. जे. के समक्ष

पुलिस महानिदेशक और एक अन्य,- याचिकाकर्ता

बनाम

शमशेर सिंह, कॉन्स्टेबल नं. 731, अम्बाला शहर,-प्रतिवादी।

लेटर्स पेटेंट अपील नं. 1975 का 297

16 दिसंबर, 1976

पंजाब पुलिस नियम 1934 (हरियाणा राज्य में लागू)-नियम 13.7-भारत का संविधान 1930-अनुच्छेद 16-कांस्टेबल की पदोन्नति के लिए अधिकतम आयु 30 निर्धारित करना-क्या यह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है।

(बहुमत के अनुसार रेड्डी और शर्मा जे. जे., संधवालिया, जे. कंट्र्रा) कि भारत के संविधान 1950 का अनुच्छेद 16 (1) गारंटी देता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अवसर की इस समानता को पूर्ण समानता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 16 (1) किसी भी रोजगार या किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए उचित नियमों के निर्धारण को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह कर्मचारियों के चयन के लिए उचित आधार पर उनके उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है। यह न केवल शैक्षिक और तकनीकी, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, आयु, अनुशासन की भावना, नैतिक अखंडता, संविधान और राज्य के प्रति निष्ठा आदि जैसे मानसिक उत्कृष्टता की नियुक्ति के लिए योग्यताओं के निर्धारण को प्रतिबंधित नहीं करता है। प्रशासनिक अभिकरण आम तौर पर किसी पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का सबसे अच्छा न्यायाधीश होता है और न्यायालय समान अवसर से इनकार करने के आधार पर ऐसी योग्यताओं के निर्धारण में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि संबंधित अभिकरण द्वारा इसका घोर दुरुपयोग नहीं किया जाता है। पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 13.7 की शक्तियों की जांच करने में यह ध्यान रखना होगा कि सिपाही 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच पुलिस बल में प्रवेश करते हैं और इस नियम के तहत उन्हें पदोन्नति के लिए चुना जाना चाहिए, इससे पहले कि वे 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें या बिल्कुल भी नहीं। यह सच है कि पदोन्नति के लिए अधिकतम 30 वर्ष की आयु निर्धारित करने से काफी संख्या में कांस्टेबलों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि उनका चयन नहीं किया जाता है, तो उन्हें 28 वर्ष की लंबी अवधि के लिए सेवा में ठहराव का सामना करना पड़ता है। इससे उन लोगों में हताशा पैदा हो सकती है जो पदोन्नति के लिए चुने जाने में विफल रहते हैं। दूसरी ओर, एक कांस्टेबल की पदोन्नति के लिए चयन के लिए अधिकतम 30 वर्ष की आयु का निर्धारण इंगित करता है कि नियम बनाने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक एजेंसी पदोन्नति के इच्छुक कांस्टेबलों से उनकी प्रतिभा और उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता के प्रदर्शन की उम्मीद करती है। जाहिर तौर पर, प्रशासनिक एजेंसी का विचार है कि पदोन्नति के लिए केवल उन्हीं का चयन किया जाना चाहिए जो शुरू से ही ऐसे गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें पुलिस सेवा में उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित किया जाता है। चूंकि आम तौर पर सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम

आयु 27 है, इसलिए प्रत्येक कांस्टेबल के पास ग्रेड बनाने का कम से कम एक मौका होता है, ताकि उसे पदोन्नति के लिए चुना जा सके, एक कांस्टेबल के रूप में नामांकन पर उसकी उम्र के आधार पर अवसरों की संख्या यह शिकायत नहीं कर सकती है कि जिन लोगों ने युवा को भर्ती किया है, उनके पास बड़ी संख्या में अवसर हैं। किसी को भी पदोन्नत होने का मौलिक अधिकार नहीं है; किसी को केवल पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। इसलिए हेड कांस्टेबल के पद पर कांस्टेबलों की पदोन्नति के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित करना इतना अनुचित नहीं है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 16 (1) का उल्लंघन बताते हुए निरस्त किया जाए।

(पैरा 13 और 14)

अभिनिर्धारित किया गया (प्रति संधवालिया, जे. कंट्र्ा) कि संविधान का अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह अच्छी तरह से तय है कि इसमें न केवल नियुक्ति के स्तर पर अवसर की समानता शामिल है, बल्कि उच्च पद पर प्रगति के बाद के चरणों में भी शामिल है। अब यह स्पष्ट है कि नियम 13.7 30 वर्ष की आयु के करीब आने वाले कांस्टेबल के लिए भविष्य की सभी पदोन्नति के खिलाफ एक बार बनाता है। यह नियम पुलिस बल में कांस्टेबलों को पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए दो वर्गों में विभाजित करने के लिए एक तीखी रेखा खींचता है, i.e जो लोअर स्कूल कोर्स शुरू होने के समय 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जो उस आयु से कम हैं। जबकि बाद वाला वर्ग हेड कांस्टेबल के लिए पदोन्नति के पहले चरण के लिए पात्र है और उसके बाद उच्च रैंक पर हो सकता है, दूसरे वर्ग को उनकी सेवा की शेष अवधि के लिए किसी भी उच्च रैंक पर बढ़ने से लगातार प्रतिबंधित किया जाता है जो आम तौर पर लगभग 30 वर्षों तक विस्तारित होता है। इस प्रकार, पुलिस बल में शामिल होने के बाद पहली पदोन्नति के उद्देश्य से भी 30 वर्ष से ऊपर के लोगों और उससे नीचे के लोगों के बीच स्पष्ट भेदभाव है। इसके अलावा पुलिस नियमों के नियम 12.24 में 30 वर्ष से कम आयु तक एक स्रोत से भर्ती का प्रावधान है। दूसरी ओर, नियम 12.15,27 वर्ष की आयु तक पुलिस बल में शामिल होने के लिए रंगरूटों को अनुमति देता है और यहां तक कि आमंत्रित करता है और आगे आम तौर पर और विशेष रूप से आयु सीमा में छूट प्रदान करता है। एक बार 30 वर्ष की आयु सीमा के साथ पुलिस बल में शामिल होने के लिए रंगरूटों को अनुमति देने या आमंत्रित करने के बाद, प्राधिकरण के लिए यह कहना उचित नहीं है कि वे अपनी सेवा के शेष लगभग तीन दशकों के लिए पदोन्नति के लिए अयोग्य होंगे। नियम 13.7 उन भर्तियों के मार्ग में पदोन्नति के लिए एक खाली और अप्राप्य हुंडई का निर्माण नहीं कर सकता है, जिन्हें 30 वर्ष की आयु सीमा पर पुलिस बल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है और यहां तक कि आमंत्रित किया गया है, और फिर भी उचित कहा जाता है। आयु का ऐसा प्रिस्क्रिप्शन, जैसा कि आवश्यक रूप से है, भर्ती के अनुमेय ऊपरी स्तर के साथ, उच्च पद पर पदोन्नति के अवसर की समानता को पूरी तरह से भ्रामक बना देगा। यह प्राधिकरण के लिए खुला नहीं है कि वह सेवा में भविष्य की सभी पदोन्नतियों के लिए मनमाने ढंग से आयु सीमा निर्धारित करने के कुटिल तरीके से अनुच्छेद 16 की गारंटी को वस्तुतः निरर्थक बना दे। यदि ऐसी आयु सीमा निर्धारित की जानी है, तो इसकी तर्कसंगतता की कसौटी पर एक परीक्षण होना चाहिए। 30 वर्ष से कम की पदोन्नति की आयु निर्धारित करने के लिए कोई पर्याप्त आधार या तर्क नहीं है, जब वर्तमान जीवन में एक व्यक्ति को अपने प्रमुख जीवन में माना जाना चाहिए। इसलिए यह प्रिस्क्रिप्शन, जो या तो पदोन्नति की किसी भी संभावना को पूरी तरह से अवरुद्ध करता है या सबसे अच्छा केवल एक या दो अवसर प्रदान करता है, केवल योग्य आयु में कांस्टेबल के रूप में नामांकित व्यक्तियों को आंतरिक तर्कसंगतता की कसौटी को पूरा नहीं करता है।

(पैरा 28, 30 और 34)

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र नाथ मित्तल द्वारा सिविल रिट नं. 1 में दिनांक 10 मार्च, 1975 को पारित आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अधीन पेटेंट अपील। 1974 का 5995।

अपीलार्थियों की ओर से एच. एन. मेहतानी और वरिष्ठ उप महाधिवक्ता (हरियाणा)।

प्रतिवादियों के लिए न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता टी. एस. दोआबिया और अधिवक्ता जे. एल. गुप्ता।

<u>निर्णय</u>

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था -

ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति

(1) इस अपील में कॉन्स्टेबल के पद से हेड कॉन्स्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए आयु की ऊपरी सीमा निर्धारित करने वाले नियम के अधिकार प्रश्नगत हैं। इन मुद्दों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों में हेड कांस्टेबलों की भर्ती से संबंधित नियमों का संक्षिप्त विवरण होना आवश्यक है।

(2) पंजाब पुलिस नियम, 1934 का नियम 12.12, सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को निर्देश देता है कि वे 'पूरी तरह से अच्छी छाप वाले पुरुषों' को कांस्टेबल के रूप में नामांकित करने के लिए विशेष ध्यान दें और प्रोत्साहित करें क्योंकि प्रदर्शन का मानक और पूरे पुलिस बल की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर अपने कांस्टेबलों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कोई साक्षरता योग्यता निर्धारित नहीं है। नियम 12.4 में यह विहित किया गया है कि भर्तियां अच्छे चरित्र की होंगी। नियम 12.15 में शारीरिक मानक और आयु सीमा निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है लेकिन 17 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भी इस शर्त के अधीन भर्ती किया जा सकता है कि 18 वर्ष की आयु से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा पेंशन के लिए योग्य नहीं होगी। पंजाब राज्य में आयु की ऊपरी सीमा 25 वर्ष और हरियाणा राज्य में 27 वर्ष है। पुलिस महानिरीक्षक को विशेष परिस्थितियों में ऊपरी आयु सीमा में ढील देने का अधिकार है। जबकि कांस्टेबलों के लिए कोई साक्षरता योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, नियम 12-10 ए कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में अच्छी सामाजिक स्थिति के मैट्रिक और मजबूत परिवार के दावों के लिए उस ग्रेड में अधिकतम दस प्रतिशत पदों तक त्वरित पदोन्नति के वादे के साथ एक विशेष प्रावधान करता है यदि वे क्रेडिट के साथ भर्ती पाठ्यक्रम पास करते हैं। नियम 12-10 ए में यह भी प्रावधान है कि यदि ऐसे अधिकारी अच्छी तरह से काम करते हैं तो उनकी पुष्टि पर सीधे लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में भेजा जाएगा। नियम में आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि वे क्रेडिट के साथ भर्ती पाठ्यक्रम को पास करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें समय-पैमाने पर वापस कर दिया जाएगा और वे त्वरित पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे। नियम 12.21 में एक सिपाही को नामांकन के तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय छुट्टी देने का प्रावधान है यदि वह 'एक कुशल पुलिस अधिकारी साबित करने की संभावना नहीं रखता है'।

(3) नियम 19.2 में यह विहित किया गया है कि भर्तियों को तब तक रैंक में उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा जब तक कि वे निर्धारित किए गए छह महीने के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण से नहीं गुजरते हैं। नियम 19.3 प्रशिक्षण के समापन पर परीक्षाओं के लिए प्रावधान करता है। प्रथम या द्वितीय श्रेणी के शिक्षा प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, सफल साक्षर कांस्टेबलों की चरित्र सूची में डालने की आवश्यकता होती है। अनपढ़ सिपाहियों के मामले में, यह प्रावधान किया गया है कि यदि वे अन्य मामलों में औसत मानक से ऊपर हैं तो उन्हें रैंक में पास किया जा सकता है। रैंक में उत्तीर्ण होने के बाद, सभी भर्तियों को नियम 19.4 के तहत सशस्त्र रिजर्व के साथ छह महीने के लिए प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके बाद भी उन्हें सालाना एक महीने का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। नियम 19.3, जो महत्वपूर्ण है, यह उपबंध करता है कि प्रथम श्रेणी के

शिक्षा प्रमाणपत्र वाले कांस्टेबलों को नियम 13.5 के अधीन कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र कांस्टेबलों की सूची 'क' अर्थात् नियम 13.6 द्वारा बनाए रखने के लिए अपेक्षित सूची में प्रवेश के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के उद्देश्य से दो या तीन मास की अवधि के लिए नियम में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियम 19.3 प्रशिक्षण के अंत में आंशिक रूप से लिखित और आंशिक रूप से मौखिक परीक्षा का प्रावधान करता है। परीक्षा आयोजित करने वाले अधिकारी को प्रत्येक सिपाही की क्षमता के बारे में अपना अनुमान भी देना होता है। इन रिपोर्टों और परीक्षा के परिणामों पर विचार करने के बाद पुलिस अधीक्षक को यह तय करना होता है कि क्या एक कांस्टेबल को नियम में निर्धारित परीक्षाओं में उत्तीर्ण कहा जा सकता है। निर्णय लेने में पुलिस अधीक्षक को विशेष रूप से इस विचार से निर्देशित होने की आवश्यकता होती है कि प्रशिक्षण जो स्वचालित रूप से एक कांस्टेबल को सूची ए में जोड़ने के बाद होगा, उसका उद्देश्य हेड कांस्टेबल के पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति को पेश करना है।

(4) नियम 12.10 में यह विहित किया गया है कि हेड कांस्टेबलों की नियुक्ति नियम 13.7 और 13.8 के अनुसार चयन ग्रेड कांस्टेबलों से पदोन्नति द्वारा की जाएगी। जबकि नियम 13.7 और 13.8 हेड कांस्टेबलों के पदों पर पदोन्नति करने में चयन की विधि और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, नियम 13.5 और 13.6 कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में पदोन्नति करने में चयन की विधि और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। नियम 13.1 के खंड (1) और (2) में पदोन्नति के लिए सामान्य विचार निर्धारित किए गए हैं और कहा गया है कि एक ही रैंक में एक रैंक से दूसरे रैंक में और एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति 'वरिष्ठता के आधार पर चयन' द्वारा की जाएगी। दक्षता और ईमानदारी चयन को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक होने चाहिए। प्रत्येक मामले में विशिष्ट योग्यता, चाहे वह उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रकृति में हो या व्यावहारिक अनुभव की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। जब अन्य योग्यताएँ समान हों, तो वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उच्च अधीनस्थ रैंक की जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक विशेषताओं वाले सुशिक्षित कांस्टेबलों को त्वरित पदोन्नति प्राप्त करनी होती है। कांस्टेबल के चयन ग्रेड और हेड कांस्टेबल के पदों पर पदोन्नति को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए, सूची ए, बी और सी को नियम 13.6,13.7 और 13.8 द्वारा निर्धारित तरीके से बनाए रखना आवश्यक है।

(5) नियम 13.5 (1) कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताओं की गणना करता है और नियम 13.5 (2) नियम में उल्लिखित प्रणाली पर उनके अंकन के क्रम में आवश्यक योग्यता रखने वालों की पदोन्नति के लिए प्रावधान करता है, अर्थात शिक्षा, पाठ्यक्रम उत्तीर्ण, व्यावसायिक क्षमता और चरित्र के लिए निर्धारित सीमा तक अंक दिए जा रहे हैं। नियम 13.5 (5) नियम 12.10. A को दोहराता है और यह भी प्रावधान करता है कि शिक्षा के मैट्रिक मानक और उससे ऊपर के और असाधारण पारिवारिक दावे करने वाले कांस्टेबलों को क्रेडिट के साथ अपने भर्ती पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने पर तुरंत चयन ग्रेड में पदोन्नत किया जा सकता है। नियम 13.6 में पुलिस अधीक्षक को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए नियम 13.5 के तहत योग्य कांस्टेबलों की सूची ए बनाए रखे।

(6) नियम 13.7 प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से दो भागों में सूची बी के रूप में जानी जाने वाली सूची को बनाए रखने की अपेक्षा करता है-(1) लोअर स्कूल पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त माने जाने वाले चयन ग्रेड कांस्टेबल और (2) ड्रिल और अन्य विशेष पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त माने जाने वाले कांस्टेबल। जब भी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रिक्तियां आती हैं, तो चयन सूची बी से किया जाता है और इसे सीमा के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। आयु में वरिष्ठता को आम तौर पर सूची में प्रवेश की तारीख की परवाह किए बिना इस तरह का चयन करने में पूर्व विचार किया जाना है। यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी कांस्टेबल को उस सूची में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए जिसकी आयु ऐसी हो कि उसे सामान्य पाठ्यक्रम में 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने से

पहले प्रशिक्षण विद्यालय में नहीं भेजा जा सके। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माना जाता है। ऐसे उम्मीदवारों की सूची जिसे सूची सी के रूप में जाना जाता है, नियम 13.8 के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है। सूची की आगे जांच की जानी चाहिए और पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। नियम 13.8 यह भी प्रदान करता है कि हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति नियम 13.1 के खंड (1) और (2) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार की जानी चाहिए, जिनके प्रावधानों का हमने पहले ही उल्लेख किया है। नियम 13.3 में आगे यह उपबंध किया गया है कि 'ग' सूची में प्रवेश की तिथि सारवान नहीं होगी किन्तु योग्यता की तुलना करते समय योग्यता के उस क्रम को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। यह भी प्रावधान किया गया है कि चयन ग्रेड कांस्टेबल जिन्होंने लोअर स्कूल कोर्स पास नहीं किया है, लेकिन अन्यथा उपयुक्त हैं, उन्हें अधिकतम दस प्रतिशत रिक्तियों तक हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। हरियाणा राज्य में यह नियम स्थिति है। पंजाब राज्य में, नियम 13.7 में संशोधन किया गया है और सूची बी में प्रविष्टियां पुलिस महानिरीक्षक द्वारा परेड, सामान्य कानून, साक्षात्कार और अभिलेखों की परीक्षा के आधार पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित योग्यता के क्रम में की जानी चाहिए। नियम में यह भी प्रावधान है कि जिस वर्ष चयन किया जाता है, उस वर्ष जुलाई के पहले दिन 30 वर्ष से अधिक आयु के कांस्टेबल सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र नहीं हैं।

(7) नियम 13.9 सहायक उप-निरीक्षकों के पदों पर हेड कांस्टेबलों की पदोन्नति के लिए प्रदान करता है और नियम 13.10 उप-निरीक्षकों के पदों पर सहायक उप-निरीक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रदान करता है। नियम 13.14 उप-निरीक्षकों के विभिन्न चयन ग्रेडों में पदोन्नति प्रदान करता है और नियम 13.15 उप-निरीक्षकों के पद से निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति प्रदान करता है।

(8) इस प्रकार, जबकि साक्षर और अनपढ़ दोनों को कांस्टेबल के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, एक विशेष प्रावधान है कि यदि वे भर्ती पाठ्यक्रम को क्रेडिट के साथ पास करते हैं तो त्वरित पदोन्नति के वादे के साथ सीधे कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में सूचीबद्ध होने के लिए। सभी सूचीबद्ध कांस्टेबल प्रशिक्षण के एक पाठ्यक्रम से गुजरते हैं जिसके अंत में एक परीक्षा होती है। जो लोग परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और शिक्षा का प्रथम श्रेणी प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं, उन्हें सूची ए में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के उद्देश्य से आगे का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र कांस्टेबलों की सूची है। अतिरिक्त प्रशिक्षण की इस अवधि के अंत में, एक बार फिर एक परीक्षा होती है और इसका उद्देश्य 'हेड कांस्टेबल के पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति' का उत्पादन करना है। इसके बाद फिर से चयन की प्रक्रिया होती है। उम्मीदवारों का चयन लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किया जाता है और अंत में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति नियम 13.2 के खंड (1) और (2) में निहित सामान्य सिद्धांतों के अनुसार की जाती है।

(9) नियमों के उपरोक्त संक्षिप्त सर्वेक्षण से, यह प्रतीत होता है कि हेड कांस्टेबल के चयन की प्रक्रिया कांस्टेबल के रूप में भर्ती के साथ व्यावहारिक रूप से एक साथ शुरू होती है। नियम की योजना बहुत कम उम्र में हेड कांस्टेबलों का चयन और नियुक्ति करने के लिए शुरू से ही एक कठोर प्रशिक्षण और ड्रिल के माध्यम से सूचीबद्ध रंगरूटों को डालना और हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए उनकी क्रीम का चयन करना प्रतीत होता है। यह ऐसा है जैसे हर वह व्यक्ति जो कांस्टेबल के रूप में सूचीबद्ध होता है, सीधे हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए उम्मीदवार बन जाता है और कई चरणों में प्रशिक्षण, परीक्षण और परीक्षाओं से गुजरता है। यदि, 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले वह प्रशिक्षण, परीक्षणों और परीक्षाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक उभरता है, तो उसे सहायक उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक और निरीक्षक के रूप में आगे पदोन्नति की संभावना के साथ हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह कांस्टेबल के चयन ग्रेड में पदोन्नति की संभावना के साथ एक कांस्टेबल के रूप में रहता है और आमतौर पर, अब नहीं। हो सकता है कि वह नियम 13.8 या नियम 13.19 के तहत पदोन्नत होने की आकांक्षा रखता हो, जो पहले मेरे हाथ से छूट गया था, लेकिन जिस पर मेरे भाई न्यायमूर्ति शर्मा ने गौर किया है। नियम 13.19 उन सिपाहियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का प्रावधान करता है जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है।

(10) कश्मीर सिंह बनाम पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर और अन्य (1) पत्तार, मामले में न्यायमूर्ति ने पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.7 के उस भाग को निरस्त कर दिया (जो पंजाब राज्य में प्रवृत्त है) जो यह विहित करता है कि कांस्टेबल, सूची बी में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पात्र होने के लिए उस वर्ष जुलाई के पहले दिन 30 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए जिसमें चयन इस आधार पर किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने कहाः -

" पंजाब राज्य में, एक पुलिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है और एक कांस्टेबल को 28 वर्ष की अवधि के लिए आगे की पदोन्नति के लिए विचार से प्रतिबंधित करना अनुचित प्रतीत होता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आयु का प्रतिबंध प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य यानी कांस्टेबलों की हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति से कोई संबंध नहीं है। आयु संबंधी यह प्रावधान मनमाना है क्योंकि इसके निर्धारण का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत कांस्टेबलों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसे रद्द किया जा सकता है। "

पैटर जस्टिस के फैसले के बाद, आर.एन.मित्तल, जे. ने 1974 के सी.डब्ल्यू. नंबर 5995 में हरियाणा राज्य के एक मामले का पालन किया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत मित्तल, जे. के फैसले के खिलाफ अपील की। नरूला, सी.जे. और एम.आर. शर्मा, जे., जिन्होंने अपील स्वीकार की, ने मामले को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से पट्टर, जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता पर संदेह था। हालांकि, इसके बाद, नरूला द्वारा पट्टर, जे. के दृष्टिकोण की पुष्टि की गई। लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत पैटर, जे. के फैसले के खिलाफ दायर अपील में सी.जे. और बैंस, जे. बैंस, जे., जिन्होंने डिवीजन बेंच के लिए बात की, ने इस प्रकार कहा: -

उन्होंने कहा, "मैं एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत हूं कि नियम 13.7 (2) अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 16 से परे है। पंजाब में सिपाहियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है और यह अत्यधिक अनुचित और मनमाना लगता है कि सिपाहियों को 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 28 वर्ष की अवधि के लिए आगे की पदोन्नति के लिए विचार से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए आयु सीमा के संबंध में यह प्रावधान मनमाना है क्योंकि नियमों में इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। बल्कि आयु सीमा के इस निर्धारण से कांस्टेबलों को 30 वर्ष की आयु के बाद आगे की पदोन्नति के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिससे निराशा और जंग लग जाएगी और इसके परिणामस्वरूप पुलिस बल में अक्षमता होगी। उस स्थिति में जो सिपाही 30 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं, उन्हें कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा क्योंकि वे जानते हैं कि उनका भविष्य का करियर अवरुद्ध है क्योंकि उन्हें हेड कांस्टेबल के अगले पद पर भी पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, उच्च पदोन्नति के लिए विचार के बारे में क्या कहना है। इस प्रकार नियम 13.7 (2) का इससे प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 16 के विपरीत है। पुलिस बल में हासिल किया जाने वाला एकमात्र उद्देश्य ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दक्षता है। मैं यह समझने में विफल हूं कि 30 साल की उम्र में कांस्टेबलों के भविष्य के करियर को अवरुद्ध करके इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जबकि उनके पास अभी

भी 28 साल की सेवा बिना किसी प्रोत्साहन के है। मेरा मानना है कि नियम 13.7 (2) जहां तक यह कांस्टेबलों के लिए सूची बी में प्रवेश के लिए 30 वर्ष की आयु-सीमा निर्धारित करता है, अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 16 के अधिकार से बाहर है। "

(11) पैटर, जे. और नरूला, सी.जे. और बैंस, जे. द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण की सत्यता अब हमारे सामने रखी गई है।

(12) वर्तमान शासन के अधिकारों की चर्चा में प्रवेश करने से पहले, बार-बार प्रशासित चेतावनी (निश्चित रूप से स्वयं के लिए) को याद रखना चाहिए कि संविधान के समानता खंडों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने में, हठधर्मी और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए और संविधान को व्यावहारिक तरीके से लोगों के शासन और मामलों से संबंधित एक जीवित साधन के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए। इसलिए किसी विधि की संवैधानिकता के पक्ष में अनुमान; इसलिए यह नियम कि विधि की असंवैधानिकता की शिकायत करने वाले पक्ष को इसे स्थापित करना चाहिए; इसलिए न्यायालयों द्वारा विधायी और प्रशासनिक विवेक को दिया गया महत्व जब विधि की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो जाता है; इसलिए न्यायालय का कर्तव्य यह पता लगाना है कि वे जहां कहीं भी हों, यदि वे मौजूद हों, तो उन्हें पराजित करने के बजाय किसी विधि को बनाए रखने के कारण हैं। इन प्रसिद्ध सिद्धांतों पर किसी भी मामले के कानून का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

(13) अनुच्छेद 16 (1) गारंटी देता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अवसर की इस समानता को पूर्ण समानता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 16 (1) किसी भी रोजगार या किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए उचित नियमों के प्रिस्क्रिप्शन को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह कर्मचारियों के चयन के लिए उचित आधार पर उनके उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है। यह नियुक्ति के लिए न केवल शैक्षिक और तकनीकी जैसे मानसिक उत्कृष्टता, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, आयु, अनुशासन की भावना, नैतिक सत्यनिष्ठा, संविधान और राज्य के प्रति निष्ठा आदि योग्यताओं के निर्धारण को प्रतिबंधित नहीं करता है। प्रशासनिक एजेंसी आम तौर पर किसी पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का सबसे अच्छा न्यायाधीश होता है और एक अदालत समान अवसर से इनकार करने के आधार पर ऐसी योग्यताओं के प्रिस्क्रिप्शन में हस्तक्षेप नहीं करेगी यदि संबंधित एजेंसी द्वारा घोर दुरुपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आंध्र विश्वविद्यालय की डिग्री के कब्जे को पंजाब राज्य में नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है या यदि 18 वर्ष की आयु किसी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु के रूप में निर्धारित की गई है, जबकि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता M.A., डिग्री है, तो अदालतें आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकती हैं कि योग्यताएं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सीमित वर्ग के पक्ष में निर्धारित की गई हैं और योग्यता निर्धारित करने वाले नियम को समाप्त कर देती हैं। लेकिन अगर कोई नियम सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष और न्यूनतम योग्यता के रूप में एम.ए की डिग्री निर्धारित करता है, तो कोई भी शिकायत नहीं कर सकता है और समान अवसर से इनकार करने की शिकायत नहीं कर सकता है।

(14) हमारे समक्ष नियम की शक्तियों की जांच करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सिपाही 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच पुलिस बल में प्रवेश करते हैं और नियम के तहत, मोटे तौर पर, उन्हें पदोन्नति के लिए चुना जाना चाहिए, इससे पहले कि वे 30 वर्ष की आयु प्राप्त करें या बिल्कुल भी न करें। यह सच है कि पदोन्नति के लिए चयन के लिए अधिकतम 30 वर्ष की आयु निर्धारित करने के परिणामस्वरूप काफी संख्या में कांस्टेबलों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिनका यदि चयन

नहीं किया जाता है, तो उन्हें 28 वर्ष की लंबी अवधि के लिए सेवा में ठहराव का सामना करना पड़ता है। इससे अनिवार्य रूप से उन लोगों में हताशा पैदा हो सकती है, जो पदोन्नति के लिए चुने जाने में विफल रहते हैं। दूसरी ओर, एक सिपाही की पदोन्नति के लिए चयन के लिए अधिकतम 30 वर्ष की आयु का निर्धारण इंगित करता है कि नियम बनाने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक एजेंसी पदोन्नति के इच्छुक सिपाहियों से उनके कैरियर की शुरुआत से ही उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता का प्रदर्शन करने की उम्मीद करती है। जाहिर है, प्रशासनिक एजेंसी का विचार है कि केवल उन्हीं लोगों का चयन किया जाना चाहिए जो शुरू से ही ऐसे गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें पुलिस सेवा में उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है। यह, जैसा कि पहले ही समझाया जा चुका है, नियमों की योजना प्रतीत होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को पदोन्नति के अवसर से वंचित किया जाता है। चूंकि आम तौर पर सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 27 है, इसलिए प्रत्येक कांस्टेबल के पास ग्रेड बनाने का कम से कम एक मौका होता है ताकि उसे पदोन्नति के लिए चुना जा सके, एक कांस्टेबल के रूप में भर्ती होने पर उसकी उम्र के आधार पर अवसरों की संख्या। एक व्यक्ति, जो एक कांस्टेबल के रूप में सूचीबद्ध होता है, यह शिकायत नहीं कर सकता है कि जिन लोगों ने युवाओं को भर्ती किया है, उनके पास बड़ी संख्या में संभावनाएं हैं। किसी को भी पदोन्नत होने का मौलिक अधिकार नहीं है; किसी को केवल पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। किसी को भी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए कम से कम इतने अवसरों का मौलिक अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से सेवा में प्रवेश की उम्र पर निर्भर करता है। जो देर से सेवा में शामिल होते हैं, वे यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास पदोन्नति के लिए विचार किए जाने की उतनी ही संभावना होनी चाहिए जितनी कि युवा सेवा में शामिल होने वालों के लिए। हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे नियमों की योजना के तहत, हर भर्ती जो खुद को एक कांस्टेबल के रूप में सूचीबद्ध करता है, उसे सीधे पदोन्नति के लिए एक उम्मीदवार के रूप में माना जाता है और कैसे एक हेड कांस्टेबल के चयन की प्रक्रिया एक कांस्टेबल के रूप में भर्ती के साथ कमोबेश एक साथ शुरू होती है। यह सच है कि यदि एक सिपाही को पदोन्नति के लिए नहीं चुना गया है तो उसे 28 वर्षों तक निम्न पद पर रहना होगा, लेकिन यदि प्रशासनिक एजेंसी यह सोचती है कि पुलिस बल के भारी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और उसके सदस्यों के लिए आवश्यक धैर्य और नेतृत्व के विशेष गुणों को ध्यान में रखते हुए, उस बल का एक सदस्य जो अपने कार्यकाल की शुरुआत से अंत तक हर समय शीर्ष रूप में होना चाहिए, क्या यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक एजेंसी ने एक अनुचित नियम निर्धारित किया है? यदि प्रशासनिक एजेंसी सोचती है कि क्षमता और नेतृत्व के अन्य गुणों को जल्द से जल्द विभाजित किया जाना चाहिए और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो क्या कोई वैध अपवाद लिया जा सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक एजेंसी ने कांस्टेबल के पद से हेड कांस्टेबल के पद पर पहली पदोन्नति के मामले में मध्यम आयु के युवाओं को प्राथमिकता देने में पूरी तरह से लापरवाही से काम किया है, ताकि जिन लोगों को पदोन्नत किया जाता है, वे इतने युवा हों कि उन्हें सेवा में अच्छा करने और सीढ़ी पर चढ़ने की और संभावना हो? क्या यह कहा जा सकता है कि जब पदोन्नति के लिए चयन मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर किया जाता है तो प्रशासनिक एजेंसी योग्य पुलिस अधिकारियों को उनकी योग्यता के अनुसार तेजी से पदोन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाने में पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण थी। पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले नियम की तर्कसंगतता पर विचार करते हुए, उन लोगों पर अवांछनीय प्रभाव जो कार्रवाई के लिए नहीं चुने गए हैं, केवल विचार करने का विषय नहीं है। ऊपर हमारे द्वारा उल्लिखित अन्य विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जो उच्च पदों में सेवा की दक्षता को छूते हैं, विशेष रूप से पुलिस बल की विशेष जिम्मेदारियों और इसके सदस्यों के आवश्यक गुणों के संबंध में। विद्वान एकल न्यायाधीश, जिन्होंने कश्मीर सिंह बनाम पुलिस अधीक्षक गुरदासपुर और डिवीजन बेंच का फैसला किया, जिसने उनके फैसले की पुष्टि की, ने एकल कारक को ध्यान में रखा कि पदोन्नति के लिए आयु की ऊपरी सीमा बहुत कम होने से बल के गैर-चयनित सदस्यों में हताशा पैदा होगी और अन्य सभी कारकों को विचार से दूर रखा जाएगा। हमें लगता है कि

उनका ऐसा करना सही नहीं था। यदि अन्य कारक, जो विद्वत एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा ध्यान में रखे गए कारक के रूप में महत्वपूर्ण हैं, को भी दरकिनार कर दिया जाता है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हेड कांस्टेबल के पद पर कांस्टेबलों की पदोन्नति के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित करना इतना अनुचित है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 16 (1) का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त करने की आवश्यकता है।

(15) मामले को दूसरे कोण से देखा जा सकता है। यदि हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हैं, और जो पहले से ही कांस्टेबल के रूप में सूचीबद्ध हैं, उन्हें आवेदन करने की अनुमति नहीं है, तो वे उस कारण से समान अवसर से इनकार करने की शिकायत नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमेशा उनके लिए इस्तीफा देने और सीधे भर्ती द्वारा हेड कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए खुला रहेगा। यदि आयु की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है, तो कोई भी शिकायत नहीं कर सकता है। पुनः, यदि हेड कॉन्स्टेबलों की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा की जाती है, और सूचीबद्ध कॉन्स्टेबलों को भी प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाती है, तो सूचीबद्ध कॉन्स्टेबल शिकायत नहीं कर सकते हैं कि आयु की ऊपरी सीमा इतनी कम तय की गई है कि उनमें से कुछ के पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक या दो से अधिक अवसर नहीं हो सकते हैं। वे ऐसा इस साधारण कारण से नहीं कर सकते हैं कि आयु की ऊपरी सीमा के बारे में नियम हेड कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। क्या इससे कोई फर्क सिर्फ इसलिए पड़ता है कि हेड कांस्टेबल के पद पर सभी नियुक्तियां पदोन्नति द्वारा की जानी हैं और आयु की एक निम्न ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है जो कुछ सूचीबद्ध कांस्टेबलों के लिए उपलब्ध पदोन्नति की संभावनाओं की संख्या को बहुत सीमित कर सकती है। हम यह नहीं समझते कि क्यों और कैसे इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। कोई भी नियम जो नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में आयु की सीमा निर्धारित करता है, चाहे वह प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा, कुछ उम्मीदवारों के उन्मूलन और दूसरों की संभावनाओं को कम करने के लिए बाध्य है। केवल इसी कारण से नियम समान अवसर से इनकार करने के बराबर नहीं हो सकता है जब नियम समान रूप से लागू होता है और जानबूझकर कुछ लोगों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है।

(16) बार में चर्चा के दौरान, बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य का संदर्भ दिया गया था। उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे नियम के अधिकारों से संबंधित था जो राज्य को एक स्थायी लोक सेवक को उसकी दस साल की सेवा के अंत में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने में सक्षम बनाता है, हालांकि एक अन्य नियम था जिसमें सेवानिवृत्ति की उचित आयु निर्धारित की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि इस तरह के नियम के तहत एक स्थायी लोक सेवक की सेवा की समाप्ति, हालांकि इसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति कहा जाता है, अनुच्छेद 311 (2) के तहत हटा दिया गया था। उन्होंने इस आधार पर नियम को रद्द कर दिया कि यह अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यह मामला उत्तरदाताओं के लिए कोई सहायता नहीं है। यह सवाल कि क्या यह नियम संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिल्कुल भी नहीं था। मोहम्मद शुजात बनाम भारत संघ (3) का भी संदर्भ दिया गया था, जहां स्नातक और गैर-स्नातक के लिए पदोन्नति के लिए कोटा निर्धारित करने वाले नियम को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 16 को आहत करता है। हम कोटा निर्धारित करने वाले किसी भी नियम का सामना नहीं कर रहे हैं। नियम 13.8 का अंतिम भाग, जो लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में अधिकतम 10 प्रतिशत रिक्तियों तक हेड कांस्टेबल के रूप में उत्तीर्ण नहीं होने वाले चयन ग्रेड कांस्टेबलों की पदोन्नति को सक्षम बनाता है, कोटा-नियम नहीं है, बल्कि चयन ग्रेड कांस्टेबलों को दी जाने वाली एक सीमित रियायत है, जिन्होंने लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया है, लेकिन जिन्हें अन्यथा उपयुक्त माना जाता है।

(17) परिणाम में, हम मानते हैं कि कश्मीर सिंह बनाम पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर और पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर बनाम कश्मीर सिंह का गलत निर्णय लिया गया था। इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है और सिविल रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एस. एस. संधवालिया -

(18) मुझे अपने विद्वान भाई रेड्डी, न्यायमूर्ति द्वारा अभिलिखित संक्षिप्त निर्णय को पढ़ने का विशेषाधिकार प्राप्त है, मैं अपने संदेहों को असहमति की लंबाई तक नहीं ले जाता, लेकिन इस तथ्य के लिए कि मैं इस विचार से इच्छुक हूं कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 (हरियाणा राज्य में केबल के रूप में) का नियम 13.7 इतनी कठोरता से काम करता है कि एक पुलिस कांस्टेबल को अपने सेवा कार्यकाल के बाद के हिस्से में अगले उच्च पद पर एक भी पदोन्नति के अवसर से वंचित कर देता है, जो लगभग 30 वर्षों तक हो सकता है।

(19) तथ्य विवाद में नहीं हैं और वास्तव में, शायद ही प्रासंगिक हैं। एकमात्र मुद्दा नियम 13.7 के उस भाग की संवैधानिकता है जो यह विहित करता है कि किसी भी सिपाही को सूची 'ख' में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी आयु ऐसी है कि वह सामान्य पाठ्यक्रम में 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षण विद्यालय में नहीं भेजा जा सकता है। पंजाब पुलिस नियमावली के नियम 13.7 (जिसे इसके पश्चात् 'नियम' कहा जाता है) का सुसंगत भाग निम्नलिखित शब्दों में हैः -

13.7 सूची बी (प्रपत्र 13.7 में) प्रत्येक पुलिस अधीक्षक द्वारा भी रखी जाएगी और इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगाः -

(1) पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के रूप में उपयुक्त माने जाने वाले चयन ग्रेड कांस्टेबल।

(2) पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में ड्रिल और अन्य विशेष पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त माने जाने वाले कांस्टेबल (चयन या समय-पैमाने)।

इस सूची से चयन किया जाएगा क्योंकि पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रिक्तियां होती हैं, बशर्ते कि किसी भी कांस्टेबल को ऐसे किसी भी पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि सूची 'बी' में उसके नाम की प्रविष्टि को रेंज के उप महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। आम तौर पर आयु में वरिष्ठता को इस तरह के चयन करने में पूर्व विचार किया जाएगा, चाहे सूची में प्रवेश की तारीख कुछ भी हो, और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सूची में शामिल एक कांस्टेबल को चयन से पहले स्कूल में प्रवेश के लिए अधिक उम्र की अनुमति न दी जाए। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम और प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर प्रतिबंध सूची बी में प्रवेश के लिए शर्तों को सीमित करता है। उस सूची में किसी भी सिपाही को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसकी आयु ऐसी है कि वह सामान्य पाठ्यक्रम में 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षण विद्यालय में नहीं भेजा जा सकता है।

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

नियम 13.8 के बाद के नियम में उन सभी सिपाहियों की सूची (सूची सी) बनाए रखने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने फिल्लौर में निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है और हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र हैं। यह केवल इस सूची से है कि हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति नियमों के नियम 13.1 में निर्धारित वरिष्ठता द्वारा चयन के सिद्धांत के अनुसार की जानी है। दो नियमों 13.7 और 13.8 को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि एक कांस्टेबल, जो ऐसे समय में पात्रता सूची 'बी' में प्रवेश प्राप्त करने में विफल रहता है कि सामान्य पाठ्यक्रम में वह 30 वर्ष की आयु से पहले प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश कर सकता है, उसके बाद अपने शेष सेवा कैरियर के लिए पदोन्नति के सभी अवसरों से वंचित होगा। मान लीजिए, नियमों के तहत एक कांस्टेबल की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। इसलिए, नियम 13.7 के आक्षेपित भाग में स्पष्ट रूप से यह उपबंध है कि यदि कोई कांस्टेबल 28 या 29 वर्ष की अधिकतम आयु तक पात्रता सूची में स्थान प्राप्त करने में विफल रहता है तो वह अपनी सेवा के शेष 30 वर्षों के लिए उच्चतर पद पर पदोन्नति के किसी भी अवसर को हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए सवाल यह है कि क्या उम्र का यह मनमाना प्रिस्क्रिप्शन भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में निहित गारंटी का उल्लंघन करता है।

(20) चूंकि नियम 13.7 के आधार पर आयु के निर्धारण की वैधता चुनौती के अधीन है, इसलिए अन्य प्रासंगिक नियमों के साथ संयोजन में पढ़ने पर पहले इस प्रावधान के वास्तविक व्यावहारिक प्रभाव का पता लगाना आवश्यक है। ये पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के दो अलग-अलग स्रोत प्रदान करते हैं। नियम 12.15 पहला और प्रत्यक्षतः सामान्य उपबंध है, जो हरियाणा राज्य में यथा संशोधित किया गया है, भर्ती की ऊपरी सीमा 27 वर्ष निर्धारित करता है। हालाँकि, इस प्रिस्क्रिप्शन में भी महानिरीक्षक द्वारा विशेष परिस्थितियों में उनके द्वारा दर्ज किए जाने के लिए ढील दी जाती है और यह स्पष्ट रूप से भर्ती के सभी वर्गों पर लागू होगा। हालांकि, एक विशेष प्रावधान है जो इस नियम के नोट 2 के रूप में अनिवार्य प्रतीत होता है जो इस प्रकार हैः -

" नोट 2-राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और पूर्व सैनिकों की भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। "

ऊपर उल्लिखित छूट के लिए सामान्य और विशेष नियमों में जो महत्वपूर्ण प्रतीत होता है वह यह है कि ये ऐसी छूट के लिए ऊपरी आयु-सीमा भी निर्धारित नहीं करते हैं और यह पूरी तरह से सरकार के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाता है जब प्रासंगिक निर्देश जारी किए जाते हैं या महानिरीक्षक को आयु-सीमा में ढील देने के लिए, जैसा भी मामला हो।

(21) भर्ती का दूसरा स्रोत जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, वह नियमों के नियम 12.24 में निहित है। इसमें भारतीय सेना के घुड़सवार सेना और इन्फैंट्री रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों और आरक्षित सैनिकों की भर्ती का प्रावधान है और उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के उप-खंड (बी) के तहत इन वर्गों के लिए उम्र का सामान्य प्रिस्क्रिप्शन 30 वर्ष से कम होना है। इस प्रावधान के तहत स्वयं बल के या अन्य राज्यों के पुलिस बलों के पूर्व कांस्टेबलों की फिर से भर्ती के लिए पात्रता भी दी गई है, जिन्होंने पहले ही उन्हें छुट्टी देने की मांग की होगी। हालांकि, पंजाब के पूर्व पुलिस अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और अन्य राज्यों के पुलिस बल के पूर्व सदस्यों के मामले में भी अधिकतम 30 वर्ष की आयु के सामान्य प्रिस्क्रिप्शन में छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता को पूरा करते हों। आयु की इस विशेष छूट (जो असाधारण मामलों में पुलिस महानिरीक्षक के साथ पूरी तरह से विवेकाधीन है) को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि यह नियम भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और उसके घुड़सवार और इन्फैंट्री रिजर्विस्टों के साथ-साथ 30 वर्ष की आयु तक पुलिस बल के पूर्व सदस्यों को भी भर्ती करने की अनुमति देता है।

(22) एक कांस्टेबल के रूप में सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु-सीमा को ध्यान में रखते हुए यह याद रखने योग्य है कि नई भर्तियां सीधे रैंक में पास नहीं होती हैं, लेकिन नियमों के नियम 9.2 द्वारा निर्धारित छह महीने के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके बाद, नियम 19.3 में पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त एक अधिकारी द्वारा भर्तियों की परीक्षा का प्रावधान है जो पहले के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पढ़ाए गए प्रत्येक विषय में अंक प्रदान करेगा। भर्तियों की शैक्षिक प्रवीणता के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। नियम 19.13 फिर चयन ग्रेड से सम्मानित होने के लिए नियम 13.6 के तहत बनाए गई सूची 'ए' में प्रवेश के लिए उपयुक्त स्थिरांकों का चयन करने के उद्देश्य से दो से तीन महीने तक अलग-अलग प्रशिक्षण निर्धारित करता है। इन नियमों का संयुक्त प्रभाव यह प्रतीत होता है कि शामिल होने के बाद एक वर्ष से थोड़ी कम अवधि के लिए, एक कांस्टेबल वस्तुतः भविष्य के कर्तव्यों के लिए प्रशिक्षण के तहत रहता है।

(23) यद्यपि 'परिवीक्षा' शब्द का उपयोग कांस्टेबल के पद के संदर्भ में नहीं किया गया है, अंतिम परिणाम नियमों के नियम 12.21 के आधार पर समान प्रतीत होता है, जो निम्नलिखित शब्दों में हैः -

"12.21. एक सिपाही जिसे एक कुशल पुलिस अधिकारी साबित करने की संभावना नहीं पाई जाती है, उसे अधीक्षक द्वारा नामांकन के तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय छुट्टी दी जा सकती है। इस नियम के तहत आरोपमुक्त करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। "

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपनी सेवा के पहले तीन वर्षों के दौरान, एक कांस्टेबल के कार्यकाल की कोई निश्चितता नहीं होती है और यह अवधि वस्तुतः परिवीक्षा की अवधि होती है। यह स्थिति अपीलार्थी-राज्य की ओर से गंभीर रूप से विवादित नहीं थी और यह इस तथ्य के आधार पर अधिक है कि व्यवस्थित प्रशासनिक अभ्यास के मामले के रूप में, एक कांस्टेबल की पुष्टि केवल तीन साल की अवधि के बाद की जाती है, यानी i.e। जब वह नियम 12.21 के अधीन निर्वहन के दायरे से बाहर चला जाता है।

(24) अब हमारे समक्ष यह विवादित नहीं था कि पुलिस बल में एक सिपाही के लिए नियुक्ति प्राधिकरण संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक है और आम तौर पर एक सिपाही केवल उस अधिकार क्षेत्र के भीतर सेवा करेगा। इस प्रकार पुलिस कांस्टेबलों की वरिष्ठता केवल जिले के भीतर है और यह नियम 12.26 के संदर्भ से स्पष्ट है जो रेंज के उप महानिरीक्षक की मंजूरी के साथ एक असाधारण उपाय के रूप में अंतर-जिला स्थानांतरण का प्रावधान करता है। इसलिए, एक कांस्टेबल के पद पर एक नए प्रवेशक को पात्रता सूची 'बी' में स्थान प्राप्त करने के लिए अपने जिले में अपने अन्य सहयोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। बार में यह बताया गया कि वास्तविक व्यवहार में प्रत्येक जिले को योग्य कांस्टेबलों के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें आवंटित की जाती हैं, जिन्हें पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, फिल्लौर में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में भेजा जाता है। नियम 13.7 स्वयं यह उपबंध करता है कि निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम में सीटों की परिसीमा 'ख' सूची में प्रवेश के लिए शर्तों को नियंत्रित करेगी और सूची में नियुक्ति की तारीख के संबंध में ऐसा चयन करने में साधारण रूप से आयु में वरिष्ठता पर पूर्व विचार किया जाएगा ताकि कॉन्स्टेबलों को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिक आयु से बचाया जा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि असाधारण योग्यता वाले कांस्टेबल को पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण 30 वर्ष की आयु से पहले निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने से रोका जा सकता है। और अगर वह चूक जाता है जो कभी-कभी उसके लिए उपलब्ध एक अकेला मौका हो सकता है, तो वह बाद में अधिक उम्र का हो जाएगा और पुलिस बल में अपनी शेष 30 वर्षों की सेवा के लिए किसी भी आगे की पदोन्नति से वंचित हो जाएगा।

(25) यहाँ व्यावहारिक रूप से पदोन्नति की समानता की गारंटी को अनिवार्य रूप से कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए अनुमत ऊपरी आयु सीमा के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। नियम अनुमति देते हैं और (यदि आमंत्रित नहीं करते हैं) 27 और 30 वर्ष की आयु तक की आयु के लिए दो स्रोतों से भर्ती की अनुमति देते हैं। वे विशेष मामलों में या अनुसूचित और पिछड़े वर्गों के मामले में कानूनी अधिदेश के रूप में आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान करते हैं। अब जहां तक नियम 12.24 के तहत भर्ती के स्रोत का संबंध है, यह स्पष्ट है कि 30 वर्ष की अनुमेय आयु पर उसके तहत सूचीबद्ध एक स्थिर व्यक्ति के पास नियम 13.7 द्वारा बनाए गए बार के कारण अपने शेष करियर के लिए पदोन्नति का दूरस्थ मौका नहीं है। इसी तरह, नियम 12.15 के तहत जो महानिरीक्षक द्वारा भर्ती की सभी श्रेणियों के मामलों में आयु सीमा में छूट प्रदान करता है, इस तरह की छूट के साथ सेवा में प्रवेश करने वाले कांस्टेबल को उसके बाद पदोन्नति के पूर्ण अवरोध का सामना करना पड़ेगा। नियम 12.15 के नोट 2 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के संबंध में आयु की अनिवार्य छूट का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रावधान के लाभ के तहत सूचीबद्ध सभी कांस्टेबलों को बाद में पदोन्नति के सभी अवसरों से वंचित कर दिया जाएगा। यहां तक कि 27 वर्ष की अनुमेय आयु में भर्ती सेवा में प्रवेश करने वाली सामान्य श्रेणी के संबंध में, सूची 'बी' के लिए ग्रेड बनाने की उनकी संभावना बहुत कम है, यदि पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं है। यह ध्यान में रखना होगा कि उनकी सेवा का पहला वर्ष वस्तुतः एक प्रशिक्षण अवधि तक ही सीमित है, जबकि अगले दो परिवीक्षाधीन होंगे, जिसके भीतर उन्हें किसी भी समय छुट्टी दी जा सकती है। भले ही उसके पास असाधारण योग्यता हो, एक कांस्टेबल को ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण सूची 'बी' पर लाने से रोका जा सकता है जैसे कि जिले को आवंटित सीटों की सीमा, आयु में वरिष्ठ कांस्टेबल पहले से ही पदोन्नति के लिए कतार में हैं और आगे पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, फिल्लौर में ही लोअर स्कूल पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या की सीमा से।

26) मेरे विद्वान भाई रेड्डी के प्रति सबसे बड़े सम्मान के साथ, न्यायमूर्ति ने नियम 12.24 के तहत अनुमेय आयु में नामांकित कांस्टेबलों को पदोन्नति के किसी भी अवसर के आभासी निषेध पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने ऐसे सिपाहियों के मामले में समान परिणाम नहीं लिया है जिनके पक्ष में नियम 12.15 के अधीन साधारणतया या असाधारण रूप से आयु सीमा में छूट दी गई है। छूट के लिए इस प्रावधान का मतलब यह नहीं हो सकता था कि यह एक हाथ से दूसरे के साथ क्या देता है। नियमों द्वारा प्रदान की गई आयु में छूट इस तरह के दंडात्मक परिणामों की परिकल्पना नहीं करेगी ताकि इस तरह से नामांकित कांस्टेबलों को उनके शेष सेवा करियर के लिए आगे की पदोन्नति से रोक दिया जा सके। लेकिन, 27 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वाली भर्तियों की सामान्य श्रेणी के संबंध में भी। रेड्डी, न्यायमूर्ति ने ठीक ही कहा है -

"ऐसा नहीं है कि किसी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित किया जाता है। चूंकि आम तौर पर सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 27 है, इसलिए प्रत्येक कांस्टेबल के पास ग्रेड बनाने का कम से कम एक मौका होता है ताकि उसे पदोन्नति के लिए चुना जा सके, एक कांस्टेबल के रूप में भर्ती होने पर उसकी उम्र के आधार पर अवसरों की संख्या। "

(27) इसलिए महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या नियम 12.24 के अधीन अनुज्ञेय आयु में सेवा में प्रवेश करने वाले सिपाहियों को पदोन्नति की सभी संभावनाओं का पूर्ण निषेध उन सभी सिपाहियों के लिए है जिनके पक्ष में आयु सीमा में विधिवत ढील दी गई है, और 27 वर्ष की अनुमेय आयु में नामांकित सिपाहियों को पदोन्नति का अधिकतम एकल अवसर (जो कई अनियमितताओं के अधीन भी हो सकता है) प्रदान करते हुए, उचित वर्गीकरण की तेजाब परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं।

(28) हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 राज्य के तहत रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। अब यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इसमें न केवल नियुक्ति के स्तर पर अवसर की समानता शामिल है, बल्कि उच्च पद पर पदोन्नति के बाद के चरणों में भी शामिल है। अब यह स्पष्ट है कि नियम 13.7 30 वर्ष की आयु के करीब आने वाले कांस्टेबल के लिए भविष्य की सभी पदोन्नति के खिलाफ एक बार बनाता है। नियम पुलिस बल में कांस्टेबलों को पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए दो वर्गों में विभाजित करने के लिए एक तीखी रेखा खींचता है, जो कि निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम शुरू होने के समय 30 वर्ष से अधिक आयु के और उस आयु से कम आयु के लोग हैं। जबकि बाद वाला वर्ग हेड कांस्टेबल के लिए पदोन्नति के पहले चरण के लिए पात्र है और उसके बाद उच्च रैंक पर हो सकता है, दूसरे वर्ग को उनकी सेवा की शेष अवधि के लिए किसी भी उच्च रैंक पर बढ़ने से लगातार प्रतिबंधित किया जाता है जो आम तौर पर लगभग 30 वर्षों तक विस्तारित होता है। इस प्रकार पुलिस बल में शामिल होने के बाद पहली पदोन्नति के उद्देश्य से भी 30 वर्ष से ऊपर के लोगों और उससे नीचे के लोगों के बीच स्पष्ट भेदभाव है। नियम 13.7 पुलिस बल में कांस्टेबलों के एक ही वर्ग को केवल आयु के आधार पर दो अलग-अलग खंडों में विभाजित करता है। इसलिए, यह पदोन्नति के उद्देश्य से एक ही वर्ग के कर्मचारियों के साथ असमान व्यवहार करता है। कानूनी शब्दावली में, इसलिए, सवाल यह है कि क्या पुलिस बल के कांस्टेबलों का उम्र के आधार पर दो अलग-अलग वर्गों में विभाजन एक उचित वर्गीकरण पर निर्भर करता है या नहीं। जैसा कि मेरे विद्वान भाई रेड्डी, न्यायमूर्ति बताते हैं कि अनुच्छेद 16, हालांकि, सिविल सेवकों के बीच सैद्धांतिक या पूर्ण समानता के किसी भी नियम को निर्धारित नहीं करता है। निस्संदेह यह विभिन्न वर्गों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने की अनुमति देता है बशर्ते एक जुड़वां योग्यता संतुष्ट हो।

पहला, कि कथित विभाजन या भेद एक आंतरिक रूप से उचित मानदंड पर आधारित है और दूसरा यह कि इसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ सीधा संबंध है। इसलिए हमें नियम 13.7 के तहत पदोन्नति के लिए आयु के प्रिस्क्रिप्शन को निर्धारित करने के लिए इस दोहरे परीक्षण को संतुष्ट किया है।

(29) यह स्पष्ट है कि भेदभाव और तर्कसंगत वर्गीकरण के मुद्दे उत्पन्न होते हैं। मैं मामले के इस पहलू को विस्तृत करने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि अपीलार्थी के विद्वत वकील ने निष्पक्ष रूप से और दृढ़ता से स्वीकार किया कि यह इस न्यायालय को निर्धारित करना है कि क्या इसमें आयु का पूर्वनिर्धारण उचित था और आगे क्या यह घोषित उद्देश्य से संबंधित था या पुलिस बल की दक्षता और अखंडता में सुधार था। तथापि, मैं अपने आप को पूरी तरह से विद्वान वकील की रियायत पर आधारित नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस बिंदु पर पूर्ववर्ती की कोई कमी नहीं है (जिसका संदर्भ इसके बाद दिया गया है) कि प्रारंभिक नियुक्ति के उद्देश्य और बाद की पदोन्नति के उद्देश्य दोनों के लिए आयु की प्रिस्क्रिप्शन को तर्कसंगतता की कसौटी को पार करना होगा।

(30) यहाँ इस मुद्दे को अनिवार्य रूप से एक कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए अनुमेय आयु सीमा के दृष्टिकोण से जांचा जाना चाहिए। नियम 12.24 में केवल 30 वर्ष से कम आयु तक एक स्रोत से भर्ती का प्रावधान है। दूसरी ओर, नियम 12.15,27 वर्ष की आयु तक पुलिस बल में शामिल होने के लिए रंगरूटों को अनुमति देता है और यहां तक कि आमंत्रित करता है और आगे आम तौर पर और विशेष रूप से आयु सीमा में छूट प्रदान करता है। एक बार 30 वर्ष की आयु सीमा के साथ पुलिस बल में शामिल होने के लिए रंगरूटों को अनुमति देने या आमंत्रित करने के बाद, क्या प्राधिकरण के लिए यह कहना उचित होगा कि वे अपनी सेवा के शेष लगभग तीन दशकों के लिए पदोन्नति के लिए अयोग्य होंगे? क्या नियम 13.7 उन भर्तियों के मार्ग में पदोन्नति के लिए एक खाली और अप्रतिरोध्य बाधा खड़ी कर सकता है, जिन्हें 30 वर्ष की आयु सीमा पर पुलिस बल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है और यहां तक कि आमंत्रित किया गया

है, और फिर भी उचित कहा जाता है? मेरा विचार है कि भर्ती की अनुमेय उच्च आयु के साथ आयु के इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन, जैसा कि आवश्यक है, उच्च पद पर पदोन्नति के अवसर की गुणवत्ता को पूरी तरह से भ्रामक बना देगा। मेरा मानना है कि यह प्राधिकरण के लिए खुला नहीं है कि वह सेवा में भविष्य की सभी पदोन्नतियों के लिए मनमाने ढंग से आयु सीमा निर्धारित करने के कुटिल तरीकों से अनुच्छेद 16 की गारंटी को वस्तुतः निरर्थक बना दे। यदि ऐसी आयु सीमा निर्धारित की जानी है, तो इसकी तर्कसंगतता की कसौटी पर एक परीक्षण होना चाहिए।

(31) पहली बात जो यहाँ नज़र आती है वह यह है कि नियम इस तथ्य की पृष्ठभूमि के विरुद्ध कि वे उस आयु की सीमा पर इसी पद पर भर्ती की अनुमति देते हैं, सिपाही के पद से पहली पदोन्नति की आयु को 30 वर्ष के निम्न स्तर पर अपरिवर्तनीय रूप से निर्धारित करने के लिए कोई सिद्धांत या तर्क नहीं देते हैं। यहां तक कि 27 साल की उम्र में सामान्य श्रेणी के तहत भर्ती किए गए एक कांस्टेबल के संबंध में, उसके पास सूची 'बी' में जगह हासिल करने का सबसे अच्छा मौका है। अपीलार्थी के विद्वत वकील पर बार-बार नियमों में कुछ भी इंगित करने के लिए दबाव डाला गया था जो इस बात का संकेत या स्पष्टीकरण दे सकता है कि पुलिस बल में पहली पदोन्नति के लिए, एक या दो वर्ष से अधिक की अवधि क्यों नहीं दी जानी चाहिए; एक अनुमेय आयु पर बल में शामिल होने वाले कांस्टेबल को दिया जाना चाहिए और ऐसा न करने पर, उसके बाद उसे अपनी सेवा की शेष अवधि के लिए उसी पद पर स्थिर रहने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि अपीलार्थी का विद्वान वकील संकेत रूप से एक प्रशंसनीय उत्तर देने में भी विफल रहा।

(32) आयु के इस प्रिस्क्रिप्शन का समर्थन करने के लिए नियमों या उसके तहत बनाए गए निर्देशों में कुछ नहीं पाते हुए, मैंने अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील को इतने कठोर और किसी भी मामले में इतने कड़े नियम के लिए स्वतंत्र रूप से कोई तर्क देने के लिए आमंत्रित किया था। मुझे याद है कि इस स्पष्ट तथ्य के अलावा कोई कारण नहीं दिया जा सकता है कि नियम निर्माताओं ने अपने विवेक में नियम 13.7 के तहत इस आयु को निर्धारित किया था। मेरे विचार से, अनुच्छेद 16 के तहत संवैधानिक गारंटी के सामने नियमों के निर्माताओं का केवल आदेश अंतिम नहीं हो सकता है।

(33) अपीलार्थी के लिए विद्वत वकील के प्रति निष्पक्षता में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसने पदोन्नति के लिए इतनी कम आयु निर्धारित करने के लिए आधे-अधूरे मन से एक कारण का सुझाव दिया था, जो प्रत्यर्थी-राज्य की वापसी में एक संक्षिप्त संदर्भ भी पाता है। यह तर्क दिया गया कि निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए कठिन और खतरनाक शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है और इसलिए 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। जहां तक कथित खतरों का संबंध है, मैं यह देखने में असमर्थ हूं कि ये 29 वर्ष के व्यक्ति और दो या तीन वर्ष की आयु से उससे बड़े व्यक्ति के बीच अंतर कैसे करेंगे। न ही कोई इस बात की सराहना कर सकता है कि कैसे 30 वर्ष की आयु में अपने जीवन के चरम पर एक व्यक्ति को या तो शारीरिक रूप से विकलांग कहा जाए या किसी भी तरह से मानसिक रूप से अक्षम माना जाए, यहां तक कि पुलिस बल में हेड कांस्टेबल से उच्च पद के लिए भी नहीं माना जाए। यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना होगा कि 'बी' सूची आखिरकार केवल एक पात्रता सूची है जिसमें से हेड कांस्टेबलों के लिए बाद में चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के मूल मानदंड पर किया जाना है। एक सिपाही को 30 साल की उम्र में भी इस तरह से माने जाने से बाहर करने के लिए यह सुझाव देना होगा कि उस उम्र में, सिपाही शारीरिक या मानसिक बुढ़ापे के करीब आने लगते हैं। हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह वकालत नहीं की और न ही किया कि 30 वर्ष की आयु में, एक सिपाही को किसी भी शारीरिक या मानसिक बाधाओं के कारण पदोन्नति के योग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पुलिस बल अपने कांस्टेबलों को उनके पचास के दशक के अंत तक 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की

आयु तक भी बनाए रखता है। इसी तरह, हेड कांस्टेबल उसी उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। यह स्पष्ट है कि एक हेड कांस्टेबल के उच्च पद में, किए जाने वाले कर्तव्य कम कठिन और कम खतरनाक होंगे और यदि बल में एक कांस्टेबल को 58 वर्ष तक जाने की अनुमति दी जाती है, तो अधिक कारण है कि वह समान क्षमता और जोश के साथ अगले उच्च पद पर सेवा कर सकता है। इसलिए, कोई यह समझने में विफल रहता है कि केवल पदोन्नति के उद्देश्य से, एक अप्रतिरोध्य बाधा) को 30 वर्ष की आयु में एक कांस्टेबल के रास्ते में क्यों रखा जाता है (जब शायद उसे पुलिस बल में दो या तीन वर्ष से अधिक की सेवा नहीं होगी) उसकी पहली पदोन्नति के लिए। अपीलार्थी के लिए विद्वत वकील सेवा विधि के संपूर्ण सरगम में किसी भी नियम को हमारे ध्यान में लाने में असमर्थ था जो या तो यह बताता है कि एक व्यक्ति को अनुमेय आयु में सेवा में प्रवेश करने के बाद एक ही रैंक में अवरुद्ध किया जाएगा या अधिक से अधिक उसे अपनी सेवा के पहले दो या तीन वर्षों में एक या दो से अधिक अवसर नहीं मिल सकते हैं और [उसके बाद भविष्य की पदोन्नति से अवरुद्ध किया जा सकता है। यह हमें नहीं बताया जा सकता था कि हेड कांस्टेबल के पद के कर्तव्यों के बारे में इतना विशिष्ट क्या है कि व्यक्ति! 30 वर्ष की आयु के बाद प्रवेश करने पर वह ऐसा करने में असमर्थ या विकलांग होगा। वास्तव में, ऐसे किसी भी निष्कर्ष को नियम 13.8 (2) द्वारा स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है जो चयन ग्रेड कांस्टेबलों को 30 वर्ष की आयु के लंबे समय बाद हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत करने की अनुमति देता है।

(34) मामले के इस पहलू को सारांशित करने के लिए, मैं 30 वर्ष से कम की पदोन्नति की आयु के प्रिस्क्रिप्शन के लिए किसी भी पर्याप्त आधार या राशन का पता लगाने में असमर्थ रहा हूं, जब वर्तमान जीवन में एक आदमी को उसके प्रमुख में माना जाना चाहिए। इसलिए, यह नियम, जो या तो पदोन्नति की किसी भी संभावना को पूरी तरह से अवरुद्ध करता है या अधिकतम रूप से केवल अनुमेय आयु में कांस्टेबल के रूप में नामांकित व्यक्तियों को एक या दो अवसर प्रदान करता है, मुझे लगता है कि आंतरिक तर्कसंगतता की कसौटी को पूरा नहीं करता है।

(35) प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होने की दूसरी कसौटी को भी समान रूप से संतुष्ट करना होगा। मान लीजिए, इन नियमों को तैयार करने का उद्देश्य पुलिस की दक्षता और अखंडता को बढ़ाना है! बल देते हैं। क्या उस उद्देश्य को अवरुद्ध करके किसी भी तरह से आगे बढ़ाया जाता है; इसके अधिकांश नामांकित पुलिस कांस्टेबल 20 या 25 वर्ष की आयु में आगे की सभी पदोन्नति से? वास्तव में, यह इससे बहुत दूर है। नियम, वास्तव में, नामांकित कांस्टेबलों के बड़े निकाय के लिए राष्ट्र और हताशा का नियम बन जाता है। यह उन्हें अपनी शेष सेवा के लिए किसी भी प्रोत्साहन या पदोन्नति की उम्मीद के बिना छोड़ देगा। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस कड़े (जैसा कि मैं कठोर भी कह सकता हूं) प्रावधान का समग्र रूप से पुलिस बल की दक्षता या अखंडता को साबित करने के साथ कोई संबंध है। वास्तव में, यह अधिकांश पुलिस कांस्टेबलों को तीन दशकों से अधिक की सेवा के लिए एक भी पदोन्नति के अवसर को या तो पूरी तरह से या ऐसी शर्तों के तहत देने से इनकार करता है जो वस्तुतः एक ही भ्रम पैदा करते हैं। इस पहलू को मेरे विद्वान भाई रेड्डी, जस्टिस ने निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से नोट किया हैः -

"यह सच है कि पदोन्नति के लिए चयन के लिए अधिकतम 30 वर्ष की आयु निर्धारित करने से काफी संख्या में कांस्टेबलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि उनका चयन नहीं किया जाता है, तो उन्हें 28 वर्ष की अवधि के लिए सेवा में ठहराव का सामना करना पड़ता है। यह अनिवार्य रूप से उन लोगों में निराशा का कारण बन सकता है जो पदोन्नति के लिए चुने जाने में विफल रहते हैं। "

सम्मान के साथ, मैं कहूंगा कि ठहराव का नियम जो पुलिस बल के बड़े हिस्से को कठिनाई और भय के लिए मजबूर करता है, स्पष्ट रूप से अनुचित है क्योंकि कठोरता या दमन उसी का एक और पहलू है। यदि

नियम दमनकारी है और वास्तविक व्यवहार में पेटेंट कठोरता में परिणाम देता है, तो यह दिखाने के लिए इसके प्रवर्तकों पर है कि यह स्पष्ट रूप से उचित है और मूल रूप से समग्र रूप से बल की दक्षता और अखंडता को आगे बढ़ाने के घोषित उद्देश्य से संबंधित है। यह, जैसा कि मैंने पहले ही सूचित किया है, अपीलार्थी स्पष्ट रूप से ऐसा करने में असमर्थ रहा है। इसलिए, मेरा विचार है कि यह नियम आंतरिक रूप से तर्कसंगत नहीं होने के अलावा पंजाब पुलिस नियमों के स्पष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के साथ संबंध होने की दूसरी कसौटी को संतुष्ट नहीं करता है और वास्तव में इसके विपरीत चलता है।

(36) सैद्धांतिक रूप से, इसलिए, मुझे यह मानना चाहिए कि नियम 13.7 का प्रासंगिक भाग केवल उम्र के आधार पर एक ही वर्ग की तालिकाओं के बीच एक मनमाना रेखा खींचता है, जो पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए कानूनी रूप से अनुमेय उम्र में पुलिस बल में शामिल होने के लगभग तुरंत चरण में है। इसलिए, यह भेदभावपूर्ण है और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है जो एक वर्गीकरण पर आधारित नहीं है जिसे उचित कहा जा सकता है।

(37) जैसा कि निर्णय से ही पता चलता है, ऐसा लगता है कि मेरे विद्वान भाई रेड्डी के साथ दो चीजें भारी थीं, न्याय ने शासन के अधिकारों को बनाए रखने में, जैसा कि वह स्वयं देखते हैं कि गंभीर कठिनाई होती है। इनमें से पहला संवैधानिकता की धारणा का नियम प्रतीत होता है। निर्माण की तोप के रूप में, संभवतः इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। यहाँ जिस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए, वह यह है कि पंजाब पुलिस के नियम, जिनमें चुनौती दिए गए नियम भी शामिल हैं, संविधान से पहले और स्वतंत्रता से पहले के युग में 40 साल पहले बनाए गए थे। उस समय भारत या इंग्लैंड में अनुच्छेद 16 या उसमें निहित सिद्धांतों के समान कुछ भी कानून का हिस्सा नहीं था। एक सर्वविदित के रूप में, राजशाही की अवधारणा द्वारा सशर्त ब्रिटिश न्यायशास्त्र में क्राउन की खुशी के दौरान पद धारण करने वाले सिविल सेवक का मूल सिद्धांत उसमें निहित है। राज्य द्वारा रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की अवधारणा के लिए और यहां तक कि बाद में पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए कोई भी कानूनी गारंटी, इसलिए, मूल रूप से इसके लिए विदेशी थी। इस प्रकार, 1930 के दशक की शुरुआत में वर्तमान पुलिस नियमों को मौजूदा औपनिवेशिक और शाही पुलिस कानूनों की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया था। इसलिए, जहां तक संविधान-पूर्व विधान का संबंध है, जो ऐसे समय में अधिनियमित किया गया था जब कानून के कोई संबंधित प्रावधान मौजूद नहीं थे, और विशेष रूप से, वर्तमान पुलिस नियम शायद ही संवैधानिकता की धारणा के नियम को सख्ती से आकर्षित कर सकते हैं। क्या कोई उचित रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि एक नियम को संविधान के अनुरूप बनाया गया होना चाहिए जो प्रासंगिक समय पर अस्तित्व में होने से दूर विचार के चरण में भी नहीं था? इसलिए, जो 40 साल पहले औपनिवेशिक और शाही शासन के तहत बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार्य हो सकता था, वह अब संविधान द्वारा नागरिकों को गारंटी दिए गए मौलिक अधिकारों को देखते हुए टिकाऊ नहीं हो सकता है।

(38) प्रसिद्ध मामले में राम कृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर, मुख्य न्यायाधीश दास ने अन्य लोगों के साथ निम्नलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन कियाः -

"कि जबकि विधानमंडल की ओर से विद्यमान शर्तों के बारे में सद्भावना और ज्ञान का अनुमान लगाया जाना है, यदि कानून या आसपास की परिस्थितियों के सामने न्यायालय के संज्ञान में कुछ भी नहीं लाया गया है, जिस पर वर्गीकरण को यथोचित रूप से आधारित माना जा सकता है, तो संवैधानिकता की धारणा को हमेशा इस हद तक नहीं लाया जा सकता है कि कुछ व्यक्तियों या निगमों को शत्रुतापूर्ण या भेदभावपूर्ण कानून के अधीन करने के लिए कुछ अज्ञात और अज्ञात कारण होने चाहिए। "

रेलवे स्थापना संहिता, गजेंद्रगडकर में निहित नियमों के संदर्भ में उपरोक्त को लागू करते हुए, न्यायमूर्ति ने बहुमत के लिए बोलते हुए मोती राम डेका बनाम उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः -

" इन दो सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह समझना मुश्किल है कि अकेले रेलवे द्वारा किस जमीनी रोजगार को विवादित नियमों को तैयार करने के उद्देश्य से एक वर्ग का गठन कहा जा सकता है। यदि प्रशासनिक दक्षता या सेवा की आवश्यकताओं के विचार इस तरह के नियम के निर्माण को उचित ठहराते हैं, तो ऐसा नियम डाक और टेलीग्राफ विभाग में केवल एक उदाहरण लेने के लिए क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए था। विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि रेलवे प्रशासन या भारत संघ द्वारा दायर हलफनामों में ऐसी कोई सामग्री नहीं दी गई है जिस पर लोक सेवा के केवल एक क्षेत्र के संबंध में नियम बनाने को उचित ठहराया जा सके।क्या हुआ है कि रुपये जैसे प्रावधान। 148 (3) या रु। 149 (3) सबसे पहले रेलवे कंपनियों द्वारा बनाया गया था जब रेलवे के साथ रोजगार अनुबंध के सामान्य नियमों द्वारा शासित एक विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मामला था। राज्य द्वारा रेलवे को अपने नियंत्रण में लेने के बाद, वह स्थिति अनिवार्य रूप से बदल गई है, और इसलिए, नियम की वैधता अब अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती के लिए उजागर है। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि विवादित नियमों की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी जानी चाहिए कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। "

परिणामस्वरूप मेरा विचार है कि संविधानात्मकता का अनुमान वर्तमान मामले में अपीलार्थी के लिए कोई बड़ी सहायता नहीं है।

मेरे विद्वान भाई ने तब यह मत व्यक्त किया है कि प्रशासनिक अभिकरण अपनी आवश्यकताओं का अच्छा आकलन करता है और इसलिए इसके दृष्टिकोण को काफी महत्व और सम्मान दिया जाना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हालाँकि, वह आगे बढ़ते हुए कहता हैः

पीठ ने कहा, "क्या यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक एजेंसी ने कांस्टेबल के पद से हेड कांस्टेबल के रूप में पहली पदोन्नति के मामले में मध्यम आयु के युवाओं को प्राथमिकता देने में पूरी तरह से लापरवाही से काम किया है, ताकि जिन लोगों को पदोन्नत किया जाता है, वे इतने युवा हों कि उन्हें सेवा में अच्छा करने और सीढ़ी पर चढ़ने की और संभावना हो? क्या यह कहा जा सकता है कि जब पदोन्नति के लिए चयन मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर किया जाता है, तो प्रशासनिक एजेंसी योग्य पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति की सीढ़ी पर तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाने में पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण थी। "

बहुत विनम्रता के साथ मैं कहता हूं कि यदि इस दृष्टिकोण का सख्ती से पालन किया जाता है, तो यह विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किए गए वर्गीकरण की तर्कसंगतता या अन्यथा निर्धारित करने के लिए न्यायालय की स्वीकृत शक्ति को वस्तुतः नष्ट कर देगा। यह स्पष्ट है कि ये निकाय शायद ही कभी कोई नियम या कानून बनाते जो किसी अच्छे, बुरे या उदासीन कारण पर आधारित न हो। यदि किसी नियम या कानून के बारे में उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि में हस्तक्षेप नहीं किया जाना है, जब तक कि यह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण या पूरी तरह से अनुचित न हो, तो शायद ऐसे सभी विधानों की वैधता की जांच का दायरा लगभग भ्रामक हो जाएगा। इस प्रकार, वर्गीकरण के मुद्दे पर प्रशासनिक एजेंसी की केवल संतुष्टि ही वस्तुतः निर्णायक हो जाएगी। इसलिए, मेरा विचार है कि यदि किसी न्यायालय द्वारा एक बार यह पाया जाता है कि भेदभाव के खिलाफ निर्धारित दोहरे परीक्षण संतुष्ट नहीं हैं, तो यह न्यायालय के लिए आगे की यात्रा करने के लिए इसकी अनुचितता की डिग्री की जांच करने या आवश्यक रूप से यह ठहराने के लिए नहीं है कि यह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण या पूरी तरह से अनुचित है।

(39) अब तक यह स्थापित विधि प्रतीत होती है कि न्यायालय दो परीक्षणों को लागू करने में अंतिम मध्यस्थ हैं कि वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किया गया वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित है और आगे यह कि इस अंतर का प्राप्त किए जाने के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है। यह परीक्षण एक उद्देश्यपूर्ण है जिसे तर्क के ठंडे निर्देश के साथ लागू किया जाना है। यह प्रशासनिक अभिकरण या उस मामले में कार्यपालिका या विधायिका की केवल व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं हो सकती है और न ही होनी चाहिए कि वे किसी भी कारण से नागरिकों को वर्गीकृत करें जो वे उचित समझते हैं। परीक्षण, वास्तव में, न्यायालय द्वारा एक खुला और वस्तुनिष्ठ परीक्षण है और न कि केवल प्रशासनिक एजेंसी की एक उप-संभावित या अनुमानित तर्कसंगतता है। भेदभाव के आधार पर कानून की अदालत में चुनौती दिए गए प्रावधान को तार्किक विश्लेषण की पूरी चकाचौंध के तहत तर्कसंगतता की कसौटी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि एक अन्य संदर्भ में कहा गया है, तर्कसंगतता भी एक गुप्त गुण नहीं है और एक नियम के समर्थक, जब हमला किया जाता है, तो उसे अदालत के समक्ष खुले तौर पर और सक्षम रूप से बनाए रखने की स्थिति में होना चाहिए। कि, मेरे विचार में, अपीलार्थी चुनौती के तहत प्रावधान के संबंध में ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं।

(40) अनिवार्य रूप से पूर्ववर्ती की ओर मोड़ते हुए, सबसे पहले मोहम्मद शुजात अली और अन्य बनाम भारत संघ, 3 (ऊपर) का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें प्रशासनिक एजेंसी ने उच्च पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से एक शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने का विकल्प चुना था, जो चुनौती के अधीन था। न्यायालय के पहले के तीन निर्णयों को स्वीकार करने के बाद, न्यायमूर्ति भगवती ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

लेकिन इन निर्णयों से यह एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में नहीं रखा जा सकता है कि जब भी कोई वर्गीकरण भिन्न शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है, तो इस तरह के वर्गीकरण को मान्य माना जाना चाहिए, चाहे वर्गीकरण की प्रकृति और उद्देश्य या शैक्षणिक योग्यताओं में अंतर की गुणवत्ता और सीमा कुछ भी हो। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जीवन में ऐसे संबंध हैं जो हमेशा लचीले डिब्बे में विभाजित होने में सक्षम नहीं होते हैं। साँचे फैलते और सिकुड़ते हैं। ऐसे मामले में उचित वर्गीकरण की कसौटी को इसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू किया जाना चाहिए।

और आगे

"उच्च पद के कर्तव्यों की प्रकृति से बाध्य नहीं होने वाली शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर भेदभाव की अनुमति देना समानता खंड के सामाजिक जोर को दबाना है।"

(41) उपरोक्त अनुपात समान रूप से लागू होता है यदि कोई उक्त मामले में शैक्षिक योग्यता को वर्तमान मामले में आयु की योग्यता के साथ प्रतिस्थापित करता है। मैंने पहले भी दिखाया है कि केवल 30 वर्ष की आयु को पार करने से कोई व्यक्ति हेड कांस्टेबल के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अयोग्य या असमर्थ नहीं होगा। वास्तव में, नियम 13.8 का बाद का भाग आयु की किसी भी योग्यता के बावजूद हेड कांस्टेबल के रूप में चयन ग्रेड कांस्टेबल की पदोन्नति की अनुमति देता है। इसलिए, आयु की योग्यता किसी भी तरह से हेड कांस्टेबल के पद पर कर्तव्यों की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं है। केवल पदोन्नति के लिए एक कांस्टेबल के रास्ते में उम्र की इस योग्यता को हस्तक्षेप करने का समान रूप से अनुच्छेद 16 के जोर को दबाने का प्रभाव पड़ता है।
t
(42) मैंने पहले ही इंगित किया है कि सेवा कानूनों की विशाल श्रृंखला में से, विद्वान वकील एक भी ऐसा संकेत नहीं दे सकता था जहां एक सिविल सेवक को केवल उम्र के आधार पर 30 वर्ष की आयु में आगे की

पदोन्नति से रोका जाना था। अपीलार्थी की ओर से प्रशासनिक दक्षता या सेवा की अनिवार्यताओं के बारे में कोई विचार नहीं किया जा सकता है जो अकेले पुलिस बल में इस तरह के नियम के निर्माण को उचित ठहराए। मोती राम डेका (ऊपर 5) के मामले में उनके प्रभुओं के सामने एक समान प्रश्न उत्पन्न हुआ, जहां रेलवे * स्थापना संहिता में शासन के अधिकार चुनौती के अधीन थे। यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कि उक्त नियम ने अनुच्छेद 311 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, उनके अधिपतियों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि लोक सेवा की किसी अन्य शाखा में अपने सिविल सेवकों के लिए ऐसा नियम नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे के लिए प्रशासनिक दक्षता या सेवा की आवश्यकताओं की कोई सहमति नहीं थी जो इस तरह के असाधारण नियम के निर्माण को उचित ठहरा सके और इसे 'समानता' खंड का उल्लंघन माना। मेरे विचार से यही तर्क वर्तमान मामले में भी उतना ही आकर्षित है।

(43) ए. नोरोन्हा बनाम. मैसूर राज्य और अन्य, (6) उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए 52 वर्ष के उच्च स्तर की आयु की योग्यता को चुनौती दी गई थी। पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति हेगड़े ने उस मामले के विशेष संदर्भ में उस नियम को संकीर्ण रूप से बरकरार रखा, जहां सेवानिवृत्ति की आयु केवल 55 वर्ष थी। यह स्पष्ट किया गया था कि इसके पीछे एकमात्र तर्क यह हो सकता है कि सार्वजनिक हित की सेवा नहीं की जाएगी यदि किसी पद पर पदोन्नत होने वाला अधिकारी केवल उस पद में कोई रुचि नहीं रखता है जिसमें उसे पदोन्नत किया गया था। क्या यह कहा जा सकता है कि यदि हेड कांस्टेबल के अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है तो पुलिस बल में 28 वर्ष से अधिक की सेवा वाला एक कांस्टेबल केवल राह का एक पक्षी होगा?

(44) इस न्यायालय के भीतर अब तक आयु के इस तरह के मनमाने निर्धारण के मुद्दे पर एक आभासी सर्वसम्मति रही है। राम लाभया, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक, और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में, तुली, जे. के समक्ष मुद्दा समान था और A.S.I के पद पर आगे की पदोन्नति के लिए सूची 'डी' पर लाए जाने के लिए हेड कॉन्स्टेबल्स के लिए 40 वर्ष की आयु के प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित था। प्रासंगिक मामला कानून को ध्यान में रखते हुए, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः -

"पंजाब राज्य में, एक पुलिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है और किसी व्यक्ति को 18 वर्ष की अवधि के लिए आगे की पदोन्नति के लिए विचार से प्रतिबंधित करना पूरी तरह से अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन प्रतीत होता है।

और फिर,

इसलिए, मेरा मानना है कि हेड कांस्टेबलों के लिए 40 वर्ष की आयु का प्रिस्क्रिप्शन, जिसे प्राप्त करने पर उन्हें संशोधित नियमों के नियम 13.9 के तहत हेड कांस्टेबलों के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम के लिए विचार करने से वंचित किया जाता है, असंवैधानिक है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त दृष्टिकोण को राज्य की ओर से लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती दी गई थी। हालांकि, महाजन और सूरी, जे. जे., जिन्होंने बेंच का गठन किया, ने L.P.A. को खारिज कर दिया। नं. 1972 का 437 (पंजाब राज्य आदि) v. जय किशन खन्ना) 25 सितंबर, 1973 को। उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति अस्वीकार कर दी गई और राज्य ने आगे कोई अपील नहीं की और इस प्रकार उक्त निर्णय अंतिम था।

(45) जहां तक नियम 13.7 में इस विशेष प्रावधान का संबंध है, यहां आयु के निर्धारण को कश्मीर में पटार, जे द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था। पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर, (1) (supra). मुख्य

न्यायाधीश नरूला और न्यायमूर्ति बैंस ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ इस फैसले की बिना किसी हिचकिचाहट के पुष्टि की - (8).

पंजाब में कांस्टेबलों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है और यह अत्यधिक अनुचित और मनमाना लगता है कि 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कांस्टेबलों को 28 वर्ष की अवधि के लिए आगे की पदोन्नति के लिए विचार करने से रोक दिया जाता है। इसलिए आयु सीमा के संबंध में यह प्रावधान मनमाना है क्योंकि नियमों में इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। बल्कि आयु-सीमा के इस निर्धारण से कांस्टेबलों को 30 वर्ष की आयु के बाद आगे की पदोन्नति के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिससे निराशा और अविश्वास पैदा होगा और इसके परिणामस्वरूप पुलिस बल में अक्षमता पैदा होगी। उस स्थिति में, जो कांस्टेबल 30 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं, उन्हें कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा-क्योंकि वे जानते हैं कि उनका भविष्य का करियर अवरुद्ध है क्योंकि उन्हें हेड कॉन्स्टेबल्स के अगले पद पर भी पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, उच्च पदोन्नति के लिए विचार के बारे में क्या कहना है। इस प्रकार, नियम 13.7 (2) का इससे प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 16 के विपरीत है। पुलिस बल में हासिल किया जाने वाला एकमात्र उद्देश्य ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दक्षता है। मैं यह समझने में विफल हूं कि 30 साल की उम्र में कांस्टेबलों के भविष्य के करियर को अवरुद्ध करके इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जबकि उनके पास अभी भी बिना किसी प्रोत्साहन के 28 साल की सेवा है। यह बार या उम्र पर प्रतिबंध समझ से बाहर है क्योंकि इन नियमों को तैयार करने से कोई उद्देश्य हासिल नहीं होगा। एक सिपाही पर उसके जीवन के इतने शुरुआती चरण में प्रतिबंध लगा दिया गया है कि इसने उसे अपने पिछले 28 वर्षों के सेवा जीवन के दौरान किसी भी पदोन्नति के अवसर से वंचित कर दिया है। यह, किसी भी तरह से, इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं रखता है।

मैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, उपरोक्त टिप्पणियों से सहमत हूं। पारित करते हुए, यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया गया था और राज्य ने स्पष्ट रूप से विशेष अनुमति के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना था।

सिद्धांत रूप में और पूर्ववर्ती दोनों रूप में मेरा मानना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय असाधारण है। अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है। पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

एम. आर. शर्मा, न्यायमूर्ति

(46) पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए तैयार सूची 'बी' की तैयारी से संबंधित पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.7 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि "किसी भी कांस्टेबल को उस सूची में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसकी आयु ऐसी है कि वह सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं है उसे 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षण विद्यालय में भेजा जा सकता है। कश्मीर सिंह के मामले में (ऊपर) पट्टार, जे, ने माना कि यह नियम संविधान का उल्लंघन था क्योंकि यह मनमाना था और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं था, i.e., हेड कांस्टेबल के पदों पर कांस्टेबलों की पदोन्नति। इस फैसले के बाद, चैंबर्स में इस मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार कर लिया। हरियाणा राज्य ने एक प्रार्थना के साथ अपील

की है कि इस नियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा जाना चाहिए और कक्षों में विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

(47) अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन रोजगार से संबंधित मामलों में सभी शहरों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह स्थापित कानून है कि किसी नागरिक को न केवल सेवा में उसके प्रारंभिक प्रवेश के समय अवसर की समानता प्रदान की जानी चाहिए, बल्कि वह पदोन्नति आदि सहित अपने सेवा जीवन के बाद के चरणों में भी समान समानता का हकदार है। हालांकि, यह राज्य के लिए खुला है कि वह सेवाओं में भर्ती के लिए उम्मीदवारों का उचित वर्गीकरण करे, साथ ही उच्च पद पर उनकी बाद की पदोन्नति के लिए भी। जहाँ राज्य वर्गीकरण आदि के बारे में उपयुक्त नियम बनाता है। नियुक्ति या पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए, ऐसे नियमों के आधार पर राज्य की कार्रवाई को इस अनुच्छेद में निर्धारित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि ऐसे नियम उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं जो सेवा में शामिल होने के इच्छुक हैं या जो पहले से ही सेवा में हैं, आगे की पदोन्नति पर नजर रखते हैं। यह देखने के लिए कि क्या नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने उचित वर्गीकरण किया है या नहीं या क्या किए गए वर्गीकरण का उस उद्देश्य के साथ कोई संबंध है जिसे नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने प्राप्त करना चाहा था या नहीं, सेवा की प्रकृति, उन कर्तव्यों की जांच करना आवश्यक हो जाता है जिन्हें करने के लिए उसे बुलाया जाता है, और सेवा से संबंधित अन्य विशिष्ट विशेषताएँ। इस संबंध में, मैं नियम बनाने वाले प्राधिकरण के दिमाग में एक झलक पाने के लिए वैधानिक नियमों को अपनाने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता था।

(48) पुलिस बल पर अपराधों का पता लगाने, कानून और व्यवस्था के रखरखाव, और समुदाय को ऐसी सेवा प्रदान करने के कर्तव्यों का प्रभार है जैसा कि समय-समय पर प्रदान करने के लिए कहा जाता है। नियम 12.12 के शब्दों में संपूर्ण पुलिस बल के कार्यनिष्पादन और प्रतिष्ठा का स्तर सब से ऊपर उसके सिपाहियों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि नियम बल की सेवा करने की योग्यता के अलावा शिक्षा और शरीर के उचित रूप से अच्छे मानक वाले अच्छे चरित्र वाले उम्मीदवारों की भर्ती पर जोर देते हैं। नियमों में यह भी प्रावधान है कि भर्ती करने वाले कांस्टेबलों को रैंक में शामिल होने की अनुमति देने से पहले ड्रिल में कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हेड कांस्टेबल, पुलिस के सहायक उप-निरीक्षकों, पुलिस के उप-निरीक्षकों आदि के पदों पर कांस्टेबलों की पदोन्नति के लिए नियमों में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। चूंकि सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर चयन एक बड़ी संख्या से किया जाता है, इसलिए नियमों को प्रतियोगिता को काफी कठोर बनाना पड़ता है। नियम 13.1 (1) के शब्दों में, "एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में और एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में एक ही श्रेणी में पदोन्नति, वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। दक्षता और ईमानदारी चयन को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक होंगे। प्रत्येक मामले में विशिष्ट योग्यता, चाहे वह उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रकृति में हो या व्यावहारिक अनुभव, पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। ..जब दो अधिकारियों की योग्यताएं अन्यथा समान हों, तो वरिष्ठ को दंडित किया जाएगा। उप-नियम (2) में कहा गया है, "इसलिए यह आवश्यक है कि उच्च अधीनस्थ रैंक की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक विशेषताओं वाले सुशिक्षित कांस्टेबलों को मान्यता प्राप्त पदोन्नति प्राप्त हो ताकि जैसे ही वे निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हो जाएं, और उनका परीक्षण किया जाए और उन्हें कांस्टेबल और हेड-कांस्टेबल के रैंक में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।

(49) यह सामान्य ज्ञान की बात है कि कम उम्र के सिपाही सक्षम अन्य रैंक और गैर-राजपत्रित अधिकारियों में ढाले जाने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। उच्च रैंक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, पुलिस बल के सदस्यों से अपराधों की जांच के उचित तरीकों और कानून के ज्ञान के बारे में अधिक जानने की उम्मीद की जाती है। कुछ महत्वहीन अपवादों को छोड़कर, तुलनात्मक रूप से कम उम्र के पुरुषों के इन

कलाओं में निपुण होने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने निर्धारित किया है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के कांस्टेबलों और 40 वर्ष से अधिक आयु के हेड-कांस्टेबलों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रशिक्षण विद्यालय में नहीं भेजा जाना चाहिए जो उन्हें आगे की पदोन्नति के लिए योग्य बनाते हैं। इन नियमों के प्रावधानों पर बल के चरित्र की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की कला में लगातार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अलावा, बल के सदस्यों को उन कठिन कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है, जिनके लिए उन्हें अवसरों पर अपनी शारीरिक ऊर्जा का अंतिम औंस लेना पड़ता है।

(50) मेरे विद्वान भाई ओ. चिनप्पा रेड्डी, जे. ने इस विषय पर नियमों का बहुत स्पष्ट विश्लेषण किया है और उस क्षेत्र को फिर से कवर करना मेरी ओर से आवश्यक हो सकता है। हालांकि, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वे कांस्टेबल, जो सूची 'बी' में अपना नाम दर्ज कराने में सक्षम हैं और जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने में असमर्थ हैं, उन्हें आने वाले सभी समय के लिए पदोन्नति प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, क्योंकि नियम 13.8 (2) में यह भी प्रावधान है कि, "चयन ग्रेड कांस्टेबल जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में लोअर स्कूल कोर्स पास नहीं किया है, लेकिन अन्यथा उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें उप महानिरीक्षक की मंजूरी से अधिकतम दस प्रतिशत रिक्तियों तक हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नियम 13.21 में यह अवधारित किया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक, यदि समीचीन समझते हैं तो व्यक्तियों के किसी वर्ग के संबंध में अध्याय 13 के उपबंधों में ढील दे सकता है। यह प्रावधान किसी दिए गए मामले में कठोरता से विचलित करने के लिए बनाया गया है। यदि पुलिस महानिरीक्षक यह राय बनाने के लिए आता है कि बड़ी संख्या में अच्छे और कुशल कांस्टेबल या कांस्टेबल अधिक उम्र के कारण पाठ्यक्रम में भाग नहीं ले पाए हैं, तो वह इस नियम को लागू कर सकता है और एक व्यक्तिगत मामले में भी छूट दे सकता है, इस संबंध में देखें श्री देश बंधु गुप्ता बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

(51) उपर्युक्त उपबंध के अतिरिक्त, पुलिस नियमों के अध्याय XV में पुलिस बल के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में विशिष्ट कृत्यों के लिए पुरस्कृत करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस तरह के पुरस्कार उन कांस्टेबलों द्वारा भी जीते जा सकते हैं जिन्हें सूची 'बी' में नहीं लाया गया है। अनुकरणीय साहस दिखाने वाले और वीरतापूर्ण कार्य करने वाले बल के सदस्यों को राष्ट्रपति पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक या पुलिस पदक से सम्मानित किया जा सकता है। नियम 13.19 (1) में कहा गया है कि प्रथम श्रेणी का पदक प्राप्त करने वाले कांस्टेबल को उस जिले में होने वाली पहली रिक्ति में हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जाएगा जिसमें वह सेवारत है, और दूसरी श्रेणी का पदक प्राप्त करने वाले कांस्टेबल को पुलिस नियम 13.19 में दिए गए चयन ग्रेड में पदोन्नत किया जाएगा।

(52) दूसरे शब्दों में, अच्छी सामाजिक स्थिति के मैट्रिक और मजबूत परिवार के दावों की भर्ती के अलावा, जिनकी भर्ती नियम 10-ए के तहत त्वरित पदोन्नति के वादे के साथ की जाती है, यदि वे क्रेडिट के साथ भर्ती पाठ्यक्रम पास करते हैं और कांस्टेबल जो 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विनियमित पदोन्नति प्राप्त करने की स्थिति में हैं, तो नियम यह प्रदान करते हैं कि चयन ग्रेड कांस्टेबल को नियम 13.8 (2) या 13.21 के प्रावधानों के तहत पदोन्नत किया जाए। नियमों में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति का पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक जीतने में सक्षम कांस्टेबलों को उनकी अन्य उपलब्धियों की परवाह किए बिना जिले में होने वाली पहली रिक्ति में हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह मान लेना उचित नहीं होगा कि एक बार जब कोई कांस्टेबल 30 वर्ष की आयु तक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने में सक्षम नहीं होता है, तो उसके लिए पदोन्नति के सभी रास्ते बाधित हो जाते हैं। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, पुलिस बल को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। यदि कोई कांस्टेबल उच्च पदोन्नति प्राप्त करने के लिए एक मामले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया

है, तो भी उसके लिए आगे पदोन्नति प्राप्त करने के लिए अपने वरिष्ठों को अपनी योग्यता दिखाना संभव है। जो लोग इस सेवा में देर से शामिल होते हैं या जो लोग 30 वर्ष से कम उम्र में भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भेजे जाने के लिए आवश्यक दक्षता हासिल नहीं करते हैं, उन्हें केवल खुद को दोषी ठहराना होगा। उनके पास निराश होने का कोई वैध कारण नहीं है, क्योंकि वे खुली आँखों से सेवा में शामिल हुए थे और पूरी तरह से जानते थे कि उनका सेवा करियर नियमों के एक विशेष सेट द्वारा शासित होगा। उनकी ओर से निराशा केवल तभी उचित होगी जब सेवा नियमों को भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाए और उस मामले में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें उचित निवारण के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से रोकता है। किसी भी स्थिति में, यदि तुलनात्मक रूप से युवा कांस्टेबल ग्रेड में आते हैं और फिर भी उन्हें पदोन्नत नहीं किया जाता है, तो वे भी निराश होंगे। यदि नियमों की न्यायिक व्याख्या से हताशा से बचा जा सकता है, तो 1 निश्चित रूप से सेवा में युवा पुरुषों के मामले का विकल्प चुनना चाहेगा। ऊपर उल्लिखित हेड-कांस्टेबल के पद पर कांस्टेबलों की पदोन्नति के तीन तरीके एक समझदार अंतर पर आधारित हैं। उन लोगों को त्वरित पदोन्नति का वादा किया जाता है जो मैट्रिक हैं सामान्य पदोन्नति या विनियमित पदोन्नति का वादा किया जाता है, जो वर्ग का बड़ा हिस्सा हैं, और पदोन्नति उन लोगों को भी दी जाती है, जो 30 वर्ष की आयु तक पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं यदि वे अपने मूल्य के उच्च गुणों को पूरा करने में सक्षम हैं या यदि वे अपनी सेवा के दौरान विशिष्ट वीरता के कार्य करने में सक्षम हैं।

मेरे विद्वान भाई ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. ने ठीक ही कहा है कि संवैधानिकता की धारणा भी वैधानिक नियमों से जुड़ी हुई है। मैं आगे यह जोड़ना चाहूंगा कि भले ही राज्य द्वारा एक पक्षीय आधार पर वर्गीकरण के आधार का असफल बचाव किया गया हो, यह न्यायालय को यह पता लगाने के लिए मामले पर विचार करने से नहीं रोकता है कि वर्गीकरण उचित है या नहीं। यदि इस प्रकार के विचार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किए गए वर्गीकरण से सेवा में स्वस्थ संयोजन की भावना पैदा होती है या अन्यथा इसमें सुधार होता है, तो न्यायालय इस नियम को अनुच्छेद 16 के उल्लंघन के रूप में निरस्त करना उचित नहीं होगा। ऐसे मामलों में न्यायिक जांच का क्षेत्र अत्यंत सीमित है, क्योंकि यह माना जाता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण को अपनी आवश्यकताओं के बारे में पता है और यदि उचित जांच या जांच पर नियम उचित प्रतीत होता है, तो इसे रद्द करना न्यायालयों का कार्य नहीं है। किसी नियम की वैधता की जांच करते समय, न्यायालय को इससे प्रभावित लोक सेवक और आम तौर पर प्रशासनिक सुविधा दोनों के दृष्टिकोण से विचार करना होता है।

(53) राम शरण बनाम पुलिस उप-महानिरीक्षक और अन्य में, राजस्थान राज्य में पुलिस बल में प्रचलित त्रिस्तरीय प्रणाली को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के आधार पर भेदभावपूर्ण होने के रूप में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहाः -

"लेकिन यह आग्रह किया जाता है कि इसे दक्षता के विचारों के खिलाफ संतुलित किया जाना चाहिए, जिसके कारण पहले से ही संदर्भित पदोन्नति की तीन-स्तरीय प्रणाली विकसित हुई है और इसलिए, इस प्रणाली को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एक जूनियर हेड कांस्टेबल को पदोन्नति मिल सकती है जबकि दूसरी सीमा में एक वरिष्ठ हेड कांस्टेबल को इंतजार करना पड़ सकता है। ऊपर वर्णित विभिन्न विचारों को संतुलित करते हुए, हमें ऐसा लगता है कि राजस्थान राज्य में लागू प्रणाली राज्य में पुलिस की दक्षता के साथ-साथ प्रशासनिक सुविधा के लिए विकसित हुई है, यह अपने आप में कानून के सामने समानता से इनकार करने या सार्वजनिक सेवा में रोजगार के मामले में समानता से इनकार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, भले ही कभी-कभी ऐसा हो सकता है, इस प्रणाली के कारण कि एक रेंज में एक जूनियर हेड कांस्टेबल को कार्यवाहक सब-इंस्पेक्टर

के रूप में पदोन्नति मिल सकती है, जबकि दूसरी रेंज में एक वरिष्ठ हेड-कांस्टेबल हो सकता है! कुछ देर इंतजार करें इसलिए हम इस प्रणाली को केवल कठिनाइयों के इन संभावित मामलों के आधार पर कानून के समक्ष समानता से इनकार करने या लोक सेवा में रोजगार के मामले में समानता से इनकार करने के रूप में समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।

तर्क की समानता पर यदि कोई पुलिस कांस्टेबल, या तो सेवा में अपने पहले प्रवेश के कारण या थोड़े समय के भीतर अपेक्षित मानक प्राप्त करने की अपनी क्षमता के कारण, उस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने में सक्षम है जिसके आधार पर उसे आगे पदोन्नति प्राप्त होती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि नियमों में शुरू की गई पदोन्नति प्रणाली अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है।

(54) सुखनंदन ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य (11) में यह निर्धारित किया गया था कि प्रशासनिक प्राधिकारी के लिए किसी विशेष सेवा के लिए न केवल मानसिक उत्कृष्टता, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, अनुशासन की भावना, नैतिक अखंडता और राज्य के प्रति निष्ठा की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। के. एम. सुगत प्रसाद और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य में भी यही दृष्टिकोण लिया गया था।

(55) ऊपर वर्णित कारणों के लिए, मैं अपने विद्वान भाई ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, जे., द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हूं, वह नियम 13.7, जो एक पुलिस कांस्टेबल के लिए 30 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित करता है सूची 'बी' पर लाया जा रहा है जो उसे पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भेजे जाने का हकदार बनाता है, भारत के संविधान के अंतर्गत है। तदनुसार मैं इस अपील की अनुमति दूंगा और कक्षों में विद्वान न्यायाधीश द्वारा जारी रिट को वापस लूंगा, लेकिन परिस्थितियों में पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दूंगा।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा